₹ 10
www.kewalsachtimes.com
जनवरी 2019
KEWAL SACH
TIMES
A National Magazine
भाजपा के चुनावी हार का
जिम्मेवार कौन?
हिन्दुत्व वाण से लोस चुनाव
का होगा भेदन?
RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT.-78

Kewal Sach
हिन्दी मासिक पत्रिका
www.kewalsach.com

Times
द्विभाषीय मासिक पत्रिका
www.kewalsachtimes.com

Live.in
PORTAL NEWS

SAMAJIK SANSTHAN
NGO
www.ks3.org.in

SHRUTI COMMUNICATION TRUST
www.shruticommunicationtrust.org

खबर वही जो सिर्फ केवल सच हो

सपने, सेवा पहली प्राथमिकता

जो केवल सच हो।

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh,
Patna- 8000 20 (Bihar) 9431073769, 9308727077
Jharkhand State Office:- Sector- 1, Block - 22, Flat No.- 303, Khelgaon Houseing Colony, Ranchi - 835217 (Jharkhand)
Ranchi Phone No.- 9431073769, 9308727077, 0612/3240075,
West Bengal Office :- Centre Point, Room No. - 208, 21 Hemant Basu Sarani,
Kolkata - 700001 (West Bengal), Ph.-09433567880, 09339740757

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894

नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951

विद्या बालन
01 जनवरी 1978

ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955

दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986

विपाशा वसु
07 जनवरी 1979

ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966

फराह खान
09 जनवरी 1965

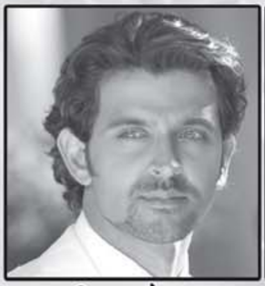

हतीक रौशन
10 जनवरी 1974

राहुल द्रविड
11 जनवरी 1973

स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863

प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972

राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963

मायावती
15 जनवरी 1956

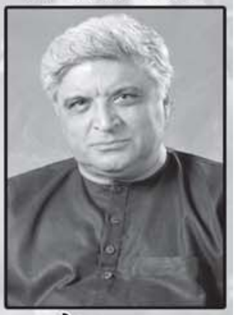

जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945

सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897

बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926

बॉबी दिओल
27 जनवरी 1967

लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865

प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769, 09308727077
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Sector- 1, Block - 14, Flat No.- 501, Khelgown Houseing Colony, Ranchi - 834009 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, 97A, DDA Flat, Gulabi bagh, New Delhi- 110007
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

05 साल में ही क्यों कमजोर हो गये

मोदी..!

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

गुजरात का शेर आखिर दहाड़ना क्यों बंद कर दिया? क्या हो गया जिससे समझौता करने की स्थिति उत्पन्न हो गयी? राष्ट्रवाद एवं हिन्दूओं के प्रणेता 05 साल के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आते ही कमजोर कैसे हो गया? नोटबंदी और जीएसटी का फैसला करने वाला राम मंदिर एवं धारा-370 पर बौना क्यों दिख रहा है? मित्रों, भाई - बहनों के संबोधन में वह ऊर्जा क्यों नहीं दिखती? क्या गंगा मईया ने यही सब करने को गुजरात से काशी बुलायी थी? हर - हर मोदी, घर - घर खोदी और अरूण जेटली - चाय की केतली सच में हो गये? 05 राज्यों के चुनाव के हारे, होश ठिकाने आ गये? देश के शीर्ष पर दलित की राजनीति विफल हो गयी? दलितों के लिए जान दे दूंगा की गर्जना करने वाले मोदी को आखिर सवर्ण की चिन्ता क्यों सताने लगी? अब भारत माता की जय एवं वंदे मातरम् का राजनीति से वोट नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला की वजह से जय श्रीराम के बजाय जय श्रीकृष्ण की राजनीति होगी? अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा - काशी है की राजनीति अब भाजपा नहीं करेगी? सच में मोदी भारत को हिन्दू राष्ट्र के बजाय धर्मनिरपेक्ष देश को मजबूत बनायेंगे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान सच में मोदी की दहाड़ से बिल में छिप गया है? ऐसे हजारों सवाल हैं जिसका जवाब न तो 2014 में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर काबिज नरेन्द्र दामोदर दास मोदी दे पा रहे हैं और न ही उनका खासम-खास भाजपा के वर्त्तमान चाणक्य अमित शाह वैसे में उनके भक्तों की हालत तो बद से बदत्तर दिख रही है। सरकार में आते ही विपक्ष को झटका से कहीं ज्यादा देश की जनता को मोदी ने लगातार और बार-बार दिया है। आज भी लोग नोटबंदी के लाईन को नहीं भूले हैं और जीएसटी का उतार-चढ़ाव प्रतिदिन मोदी की सरकार के लिए नासूर का काम कर रहा है जबकि न तो नोटबंदी से पत्थरबाजी कम हुई और न ही जीएसटी से देश का कर एक हुआ। गैस सिलेण्डर की सही किमत आज भी कुछ खास लोग ही समझ पाते हैं। जनता ने गैस सिलेण्डर पर मिलने वाले सब्सिडी को छोड़ा पर विलासता संबंधित सब्सिडी को किसी MP और भाजपा शासित राज्य के किसी MLA ने भी नहीं छोड़ा। खुद भाजपा के नेताओं के बीच भी PM मोदी एक जुमलेबाज की तरह दिखते हैं। देश के किसी विपक्ष ने मोदी को जुमलेबाज कहकर अपमानित नहीं किया जितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने किया और भाजपा का मतलब भी समझाया और महज 05 साल में जनता के बीच लोकसभा चुनाव में करारी मोदी से हार के बाद भी इतना जनाधार अचानक बढ़ा लिया की मोदी को अपने जीते 5 सीट कुर्बान करने पड़े और आधा का हिस्सेदार बनाकर बिहार की राजनीति में मोदी का कद नीतीश कुमार के सामने बौना हो गया। मोदी के राज्य में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा दागदार हो गया क्योंकि मोदी ने स्वयं मुख्यमंत्री से अधिक भरोसा मुझपर करे मन की बात कहकर जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान में बसुंधरा राजे सिंधिया पर उसके राज्य के लोगों को भरोसा नहीं था पर मोदी ने जनता की मांग को खारिज कर दिया जिसको चुनाव में जनता ने खारिज कर दिया। झारखण्ड में भी बिहार में कद छोटा होने से 10 सीट से अधिक नहीं जीत पायेंगे और झारखण्ड में मुख्यमंत्री की करतूत और भ्रष्टाचार के साथ अहंकार भी 5 सीट पर ही समेट देगा की स्थिति दिख रही है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा की राजनीति करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश का उत्तर प्रदेश की रामभक्त जनता ने 2014 में 72 सीट पर जय श्रीराम को शक्ति दी थी पर 5 साल में जनता को जय श्रीराम को न्याय नहीं दिलाना और रामभक्त हनुमान को दलित बिरादरी तय करने का भी दंड भुगतना पड़ सकता है। 72 तो दूर 50 सीट पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। गंगा मईया भी अभी मैली है और इसके पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। गंगा मइया के दम पर व्यापार करने की सोच स्वच्छ गंगा की सच्चाई सामने आने लगी है। वोट के लिए राष्ट्र को भी दांव पर लगाया जा सकता है और जिस देश का प्रधानमंत्री यह दावा करता रहा है कि जान दे दूंगा पर आरक्षण समाप्त नहीं करूंगा और देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां तक कहते हैं कि जिसको जहां जाना है जाये लेकिन आरक्षण पर समीक्षा भी संभव नहीं है। 05 राज्य में मिली करारी हार की वजह नोटा को माना गया जिसको खुश करने का प्रयास सवर्ण या सामान्य को 10 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा से पास हो जाने के बाद भी मोदी की कार्यशैली से नाराज लोगों का वोट उन्हें हासिल होगा प्रश्न ही लग रहा है। 40 सीट बिहार - 14 सीट झारखण्ड और 80 सीट उत्तरप्रदेश मिलाकर पिछले 2014 लोकसभा चुनाव 134 सीटों में 98 प्रतिशत सीटों पर भाजपा का ही कब्जा था लेकिन अब इन तीनों राज्यों में ही मोदी का लहर शांत होता दिख रहा है। भाजपा की पहचान एवं वजूद हिन्दूवादी छवि एवं राष्ट्रीय भावना का कद्र करने की थी लेकिन राम मंदिर का निर्माण एवं धारा 370 का फैसला जब कराने में कामयाब नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट का फैसला से ही होगा तो फिर कैसा राष्ट्र एवं धर्मवाद? विदेशों में मोदी-मोदी-मोदी की गूंज से भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार और पाकिस्तान की शैतानी गतिविधियों में कमी नहीं आती दिख रही है जबकि 56 ईंच के सीने से असंख्य उम्मीदें देशवासियों की लगी थी। कुछ ऐसे फैसले जिसके लिए जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था उसको पूरा करने के बजाय कई कठोर फैसले लेकर जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया और यही कारण है की 5 ही साल में मोदी जी कमजोर दिखाई दे रहे हैं।

लोकसभा चुनाव 2019 की डुगडुगी बज चुकी है और सभी दल देशभर के वोटरों को अपने पक्ष में करने का हथकंडा अपना रहे हैं। एक तरफ अकेले मोदी खड़े हैं तो दूसरी तरफ देश का 90 फिसदी राजनीतिक दल महागठबंधन बनाकर एनडीए से कहीं ज्यादा मोदी को शिकस्त देना चाहता है। मोदी को देश की जनता ने 2014 में प्रचंड बहुमत दिया था ताकि पाकिस्तान से आंख में आंख मिलाकर कश्मीर समस्या का हल और धारा- 370 की समस्या को समाप्त हो जायेगा तो अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्मभूमि का विवाद समाप्त होकर मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जायेगा पर 05 साल की सरकार में टोपी नहीं पहनने वाले PM मोदी ने जितनी सक्रियता नोटबंदी और जीएसटी के साथ कांग्रेसमुक्त भारत बनाने में लगायी और मुख्य मुद्दा से मोदी भटक गये और लोकसभा चुनाव 2019 के एक साल पहले नया मुद्दा दलित और आरक्षण को बनाकर राम मंदिर और धारा - 370 से खुद को अलग करता दिखा और ओवैसी जैसी बीमारी को भारत में लाने के लिए भी जनता मोदी को ही जिम्मेवार मानती है। PM मोदी आजाद भारत के सबसे प्रचंड बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री हैं जिससे मुस्लिम समाज को भय लगा और फिल्म के कई कलाकार को भारत में भय सताने लगा लेकिन सच इससे बिल्कुल इत्तर है। भारत की साख दुनिया भर में बढ़ी लेकिन भारत की वह जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है जिसने अपना विश्वास मोदी के हवाले कर दी थी। आखिर 05 साल के सत्ता में ही देश - दुनिया का दमदार मोदी किन कारणों से लाचार दिख रहा है?

ब्रजेश मिश्र

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्ष:- 08, अंक:- 91 माह:- जनवरी 2019 रू. 10/-

Editor in chief

Brajesh Mishra 09431073769
09955077308
09308727077

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Chief Editorial Advisor
Deepak Mishra 09334096060

General Manager (H.R)
Triloki Nath Prasad 9308815605,
9122003000

General Manager (Advertisement)
Reeta Singh 09308729879
Poonam Jaiswal 09430000482

Joint Editor/Lay-out Editor
Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor
Amitabh Ranjan Mishra 08873004350
S. N. Giri 09308454485

Asst. Editor
Rampal Prasad Verma 0 9939086809

Bureau Chief
Sanket kumar Jha 07762089203

Photographer
Mukesh Kumar 9304377779

Bureau
Sridhar Pandey 09852168763

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड
राजेश मिश्रा 09608645414
08083636668
rajeshmishrarti@gmail.com

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 09433567880
09339740757

मध्यप्रदेश हेड
अभिषेक पाठक 08109932505,
08269322711

छत्तीसगढ़ हेड
डिगल सिंह 09691153103
08982051378

उत्तर प्रदेश हेड
निर्भय कुमार मिश्रा 09452127278

उत्तराखण्ड हेड
आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड
कमोद कुमार कंचन 07492868363

गुजरात हेड
आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड
श्रवण कुमार चंचल 08977442750

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

पंजाब हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

उड़ीसा हेड
आवश्यकता है

आसाम हेड
आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
सेक्टर- 1, ब्लॉक नं.-22,
फ्लैट नं.-303,
खेलगांव, होटवार, राँची- 834009
मो०- 9955077308, 9431073769

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 07492868363

आंध्र प्रदेश

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- श्रवण कुमार चंचल
एस के प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज,
प्लॉट संख्या-116, रोड नं.- 25,
आई पी काटेदान,
जिला-रंगारेड्डी, हैदराबाद-500077
मो०- 09700475872, 07842218598

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास, बेलभाँटा,
अभनपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो०- 09835845781, 08602674503

आपको केवल सच टाइम्स पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारी सच्चाई है।

हमारा पता है

केवल सच टाइम्स,

द्विभाषीय मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769, 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

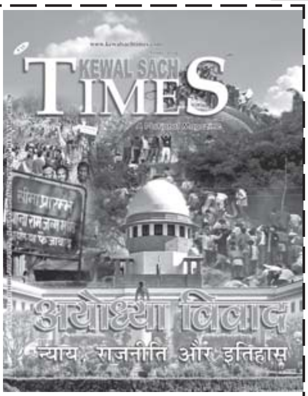

दिसम्बर 2018

याद आयेंगे बाजपेयी जी

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका की खबर को पत्रकार उसको और खास बना देते हैं। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री व सभी दलों में लोकप्रिय व्यक्तित्व स्व० अटल बिहारी बाजपेयी की कृति पर योजस्वी खबर को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो बधाईयोग्य है। उनके द्वारा राष्ट्रहित एवं भाजपा सहित हिन्दुओं के लिए किये गये सार्थक प्रयास की याद को आपने अपने पत्रिका में सही ढंग से सहेजने का कार्य किया है। ऐसी खबरों की वजह से ही केवल सच टाइम्स पत्रिका बाजार में अपनी साख को मजबूत कर रहा है। बड़ी होने के बाद भी उबाउ नहीं लगी यह खबर और संकल्ति फोटो भी संदेशात्मक लगे। लेखक को कोटि-कोटि बधाई।

● **प्रमोद मालाकार, कचौड़ी गली, बनारस, यूपी**

सच हुआ संपादकीय

ब्रजेश जी,

दिसम्बर 2018 अंक में केवल सच टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय ''कांग्रेस बचा पायेंगे राहुल..!'' में आपने संपादकीय में 05 राज्यों के चुनाव के परिणाम को पहले ही उजागर कर दिया था तथा राहुल को कैसे राजनीति करके मोदी को पछाड़ सकते हैं की भी गुर बतायी थी। कांग्रेस ने राहुल को और राहुल गाँधी ने कांग्रेस को बचा लिया है। 2014 के बाद राहुल गाँधी का कद दिनों-दिन बढ़ता ही गया है और 2019 में खुद को मोदी से मुकाबला के लिए तैयार भी कर लिया है तथा चुनाव में शिकस्त देने के गुर भी सीख लिए हैं। मोदी के लिए 2019 का चुनाव 2014 की तरह आसान नहीं होगा की जानकारी इस संपादकीय में बहुत ही सटीक एवं तथ्यपूर्ण लगी।

● **कौशलेन्द्र शाण्डिलय, इटारसी बस स्टैण्ड, भोपाल**

370 और आतंकवाद

ब्रजेश जी,

देश की जन्नत पर पाकिस्तान की गंदी नजर है और लगातार भारत पर कश्मीर के लिए हमला कर रहा पाकिस्तान को धारा 370 की वजह से सहूलियत मिलती रहती है क्योंकि वहां दूसरे प्रदेश के लिए स्थायी रूप से बस नहीं सकते। धारा 370 और आतंकवाद पर अमित कुमार की इस रिपोर्ट ने दिल को झकझोर दिया है और भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था की विवादस्पद सोच के कारण ही आतंकवाद देश को खोखला करता दिख रहा है। इस खबर में 370 के परिणाम एवं आतंकवाद का असर से भारत का कितना नुकसान एवं देश टूटने का खतरा है उसपर सटीक खबर आपकी देशहित सोच को प्रदर्शित करता है।

● **बिशंभर नाथ सिंह, अशोक बिहार, नई दिल्ली**

रंगीन पृष्ठों का अभाव

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स, पत्रिका में खबरें बहुत ही सटीक, धारदार एवं कारगर रहती है लेकिन सादा पत्रिका होने की वजह से रौनक नहीं दिखता। दिसम्बर अंक की खबर को पढ़कर मन अति प्रसन्न तो गया लेकिन रंगीन फोटो का अभाव ने खबर की धार को थोड़ा कमजोर कर दिया। खेल और फिल्म के साथ अगर फोटो रंगीन नहीं हो तो उसकी खबर में बासीपन दिखता है। कहानी एवं स्थायी आम आदमी से जुड़ी जरूरतों का स्तंभ का अभाव साफ झलकता है। यह पत्रिका अगर रंगीन पृष्ठों में आने लगे तो दूसरी स्थानीय पत्रिका के लिए केवल सच टाईम्स मील का पत्थर साबित होगा। इस अंक का सभी खबर पठनीय लगे।

● **रमेश पासवान, रोतु रोड, राँची (झारखण्ड)**

अयोध्या विवाद

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका अपनी बेबाक लेखनी की वजह से ही पाठकों के बीच अपनी साख मजबूत कर चुका है। दिसम्बर 2018 अंक का संपादकीय से लेकर सभी खबर प्रभावकारी, जानकारीप्रद एवं समीक्षात्मक लगे। ''अयोध्या विवाद - न्याय, राजनीति और इतिहास'' में अमित कुमार ने पूरी खबर की बहुत ही बेहतरीन पड़ताल की है। एक - एक तथ्य को पूरी गंभीरता एवं सत्यता के साथ रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है। केवल सच टाइम्स पत्रिका किसी भी खबर की समीक्षा तथ्यात्मक करता है जिसकी वजह से इसकी प्रमाणिकता बढ़ जाती है। पृष्ठों की संख्या की वजह से खबरों का अभाव दिखता है। अयोध्या विवाद का खबर मुझे बहुत ही धारदार एवं असरदार लगा। लेखक को स्तरीय लेख के लिए बधाई।

● **सुनील पाठक, अयोध्या, यूपी**

महागठबंधन

संपादक जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के दिसम्बर 2018 अंक में लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भाजपा + जदयू + लोजपा का बिहार का टिकट बंटवारे की खबर भी मुझे अच्छा लगा की आपने भाजपा की खबर को भी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। 17 सीट पर भाजपा एवं 17 पर जदयू के साथ लोजपा को 6 सीट एवं रामविलास पासवान को राज्यसभा की सीट में मिलाप हो गया। छोटी - छोटी खबर को स्थान देने से पाठकों को ढ़ेर सारी जानकारी प्राप्त होती है तथा पाठकों की संख्या भी बढ़ती है। इस पत्रिका में स्तंभों का अभाव दिख रहा है तथा राजनीति की अधिक खबरो का समोवश इस पत्रिका में पढ़ने को मिला। संपादकीय और धारा 370 की खबर को पढ़कर थोड़ी चिंता तो बढ़ गयी पर महागठबंधन का प्रयास से मोदी का लहर शांत नहीं होगा।

● **मनोज साव, झाउगंज, पटनासिटी, पटना**

अन्दर के पन्नों में

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक **'केवल सच'** पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स' द्विभाषीय मासिक पत्रिका
प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

मुख्य संरक्षक के लिए आमंत्रण

मुख्य संरक्षक के लिए आमंत्रण

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नंः-14, मकान संख्याः- 28/14, कंकड़बाग,पटना-800020(बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
- A/C No. :- 20001817444
  BANK :- State Bank Of India
  IFSC Code :- SBIN0003564
  PAN No. :- AKKPM4905A

एक नजर इधर भी

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

● अमित कुमार

जिस प्रकार गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद कुरूक्षेत्र में हुआ, आज ऐसा ही कुछ कृष्ण-अर्जुन के संवाद को इस चुनावी समर में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अर्जुन रूपी देश की जनता अपने पार्थ से अपने भीतर हो रहे कौतुहल को बताते हुए कहते हैं कि, हे कृष्ण! चुनावी समर आरंभ हो चुका है। रणभूमि सज चुकी है। कहीं बिगुल बज रहे हैं तो कही शंखनाद हो रहा है। चारों तरफ कोलाहल है। हम आम मतदाता, अर्जुन की तरह किंकर्तव्यविमूढ़, अपनी शक्ति से अपरिचित रणक्षेत्र में खड़े हैं। मैं क्या करूं? हर तरफ तो मेरे अपने हैं। किसे मत दूं और किसे नाराज करूं। किस पर शस्त्र प्रहार करूं और किसे बचाऊं? बेहतर है कि मैं अपने मत (नोटा) का प्रयोग ही नहीं करूं। मेरे अकेले के मत नहीं देने से कौन सा पहाड़ टूटेगा? मुझे इस रणक्षेत्र से बाहर निकालो। मुझे इस द्वंद्व में मत घसीटो। मैं बाहर ही ठीक हूं। मुझे अपना काम करने दो। छुटी का आनंद लेने दो।

पाठकों के मन में ये सहज जिज्ञासा होगी कि यह कृष्ण कौन है, जिससे अर्जुन रूपी मतदाता प्रश्न पूछ रहा है। वह कृष्ण कोई और नहीं उसकी ही अंतरात्मा, उसका विवेक या उसका चंचल मन है और सटीक उत्तर भी वही देता है। गौरतलब

हो कि वह चंचल मन और अंतरात्मा रूपी कृष्ण, अपने जनता रूपी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि, हे मेरे प्रिय भारतवासी, समाज में हो रहे हर अन्याय का दोष कलयुग पर ढोलने वाले भक्त, क्या तुम जानते हो कि मात्र कुछ दशकों पूर्व तक सत्ता का परिवर्तन बिना हिंसा के संभव नहीं था। द्वापर युग तो ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है। तुम सौभग्यशाली हो कि भारत की पवित्र भूमि के उस युग में जी रहे हो, जहां शासक को बदलने के लिए रक्तपात का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज भी विश्व के पच्चीस प्रतिशत देशों में और दुनिया के चालीस प्रतिशत से अधिक लोगों को मताधिकार का अर्थ नहीं मालूम। ऐसे देशों में सत्ता में बैठे किसी दुराचारी का तख्ता उलटने के लिए नागरिकों को जान की कुर्बानी देनी होती है। प्रजातंत्र का मूल्य वे लोग अधिक समझते हैं, जिनके भाग्य में यह नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में एक रोबोट की तरह जीवन जीते हैं, जिसकी कुंजी उनके शासक के हाथ में होती है। जैसा उन्हें खिलाया जाता है वे खाते हैं, जैसा दिखाया जाता है वे देखते हैं, जो पढ़ाया जाता है वे पढ़ते हैं। भारत में रहकर ऐसे देशों के लोगों के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। हे पार्थ, विधाता ने तो सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया किंतु मनुष्य ने ही स्वयं को रंग, वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र और समाज में विभाजित कर लिया। भयावहता तो यह है कि कुछ ऐसे चंद लोग नये धर्म की स्थापना भी करने में लगे हैं और कुछ शासक बनकर शोषक हो गए। कुछ ने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया और अन्य को हीन। सौभाग्य भारतवंशियों का यह रहा कि स्वतंत्रता के बाद जिस संविधान को उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था उसने उन्हें न केवल समान अधिकार दिए बल्कि देश और प्रदेश की शासन व्यवस्था में अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी दी। चुनने के पश्चात भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुसार जनता ने बड़े सम्मान के साथ अपने प्रतिनिधि को शासक का सम्मान दिया (जिसे सेवा का अवसर दिया, वह आका बन गया)। प्रतिनिधि भी यदि संस्कारी है तो वह प्रजातंत्र की इस व्यवस्था में अपने आप को जनता का सेवक ही समझता है, जिस तरह मोदी जी अपने आपको प्रधान सेवक एवं चौकीदार कहते हैं। किंतु हे पार्थ अर्जुन! दुर्भाग्य से कुछ प्रतिनिधियों को जीतने के बाद शासक बनने का गुरूर हो जाता है। वे प्रजातंत्र के लिए खतरा बन जाते हैं, किंतु प्रजातंत्र में शक्ति है, इस गुरूर का अंत करने की। घमंड को तोड़ने की। अनेक बार जनता ने इस शक्ति का प्रयोग भी किया है, आगे भी करेगा, क्योंकि उसके पास मत के रूप में ऐसा अमोघ अस्त्र है जहां वह बैठे-बैठे प्रदेश और देश की सरकार को उलट सकती है और कई बार हैरतंगेज परिणाम से सभी को अचंभित भी किया है। राजनीति किसी व्यक्ति या परिवार की जागीर न बने, इसलिए हर बार जनता ऐसे प्रतिनिधियों को सड़क पर ले आती है जो उनके सोच पर ग्रहण लगा देती है। प्रजातंत्र में कोई पैदाइशी शासक नहीं होता। हे अर्जुन, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के तथाकथित आधुनिक युग में प्रजातंत्र के साथ प्रेस की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था पर दुनिया भर में लगातार हमले हो रहे हैं। शासक, प्रजा के अधिकारों को कम करना चाहता है और अपने अधिकारों के दायरे में विस्तार। तुर्की और थाईलैंड जैसे देश इसके नए शिकार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 70 देशों की जनता के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गिरावट आई है, जिसमें प्रजातंत्र का चैंपियन अमेरिका भी शामिल है और ऐसा पिछले बारह वर्षो से लगातार हो रहा है। **अतः हे भारत के भाग्यविधाता**, प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में अपने मत के रूप में आहुति दे, ताकि उसकी ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहे। अपने राष्ट्र के प्रजातंत्र को मजबूत करे, भारत के प्रजातंत्र को परिपक्व करे, ताकि कोई शासक इस पर नजर न उठा सके। इस पर प्रहार न कर सके। उठो! अपना धनुष उठाओ,, अपने मत रूपी बाण का संधान करो और अपने विवेक से लक्ष्य भेद करो। तेरी विजय ही प्रजातंत्र की विजय है और तेरी हताशा प्रजातंत्र की हार।

2018 अहंकार और अति महत्वकांक्षा में एक ऐसा मामा शहीद हो गया, जिससे कंस रूपी भांजा भी संतुष्ट था। लेकिन मामा, उस महान व्यक्तित्व के बड़े बोल और क्षत्रीओं के ताल ठोकने वाला राज्य में भी राजनीतिक सोच कुछ ऐसे ही देखने को मिला। कही किसी राज्य में सीएम से ज्यादा पीएम पसंद आ रहा था कही पीएम के बड़े बोल ने सीएम की बोलती बंद कर दी। ऐसा ही बीते पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह ने चुनावी नतीजे आने के बाद हार स्वीकार करते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। इंतजार था 13 सालों से मध्यप्रदेश की सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान का। बताते चले कि मध्यप्रदेश की मतगणना 12 दिसंबर की सुबह आठ बजे तक चली। पूरी रात ऐसा लगता रहा कि

कहीं बड़ा उलट-फेर ना हो जाए। सवा आठ बजे स्थिति साफ हो गई। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच महज पांच सीटों का फर्क रहा। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। साथ ही बीजेपी के मध्यप्रदेश प्रमुख राकेश सिंह ने एक ट्वीट कर इन कयासों को और हवा दे दी। राकेश सिंह ने ट्वीट किया कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि सारे निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद भी बीजेपी बहुमत के जादुई आँकड़ों तक नहीं पहुंच पा रही थी। बीजेपी के 109 और चार निर्दलीय विधायकों को मिलाने के बाद भी संख्या 113 तक ही पहुंच पाती। मायावती ने अपने दो विधायकों और समाजवादी पार्टी ने एक विधायक का समर्थन कांग्रेस को देने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सारे विकल्पों को देख चौहान मीडिया के सामने आए और कहा कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले, लेकिन संख्या बल में हम पिछड़ गए। मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूं और अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं।

बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी और वह 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1990 में पहली बार बीजेपी ने चौहान को बुधानी से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। चौहान ने पूरे इलाके की पदयात्रा की थी और पहला ही चुनाव जीतने में सफल रहे। तब चौहान की उम्र महज 31 साल थी। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में दो जगह से खड़े थे। एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ और दूसरा मध्यप्रदेश के विदिशा से। वाजपेयी को दोनों जगह से जीत मिली। उन्होंने लखनऊ को चुना और विदिशा को छोड़ दिया। सुंदरलाल पटवा ने विदिशा के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का प्रत्याशी बनाया और वो पहली बार में ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद यहां से चौहान 1996, 1998, 1999 और 2004 के भी चुनाव जीते। चौहान को अब तक के राजनीतिक जीवन में एक बार हार का सामना करना पड़ा है। 2003 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चौहान को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघोगढ़ से खड़ा किया था, तब बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा। चौहान को भी पता था कि राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह को हराना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी की बात मानी। उमा भारती के कुल आठ महीने और बाबूलाल गौर के 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 29 नवंबर, 2005 को मध्य प्रदेश के 25वें मुख्यमंत्री के तौरपर शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद प्रदेश के तीसरे ओबीसी मुख्यमंत्री बने। इससे पहले मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री सवर्ण रहे थे। उमा भारती के छोटे कार्यकाल में उनके व्यक्तित्व के कारण पार्टी को कई बार असहज होना पड़ा था। उमा भारती के इस्तीफे को बीजेपी ने बड़ी राहत की तरह देखा था। तिरंगा प्रकरण में उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा था तो सुषमा स्वराज का एक प्रसिद्ध बयान सामने आया था, 'इट वॉज अ गुड रिडेंस।' यानी इसी बहाने पार्टी को उमा भारती से मुक्ति मिली। वही बड़ी बात यह भी थी कि शिवराज सिंह चौहान का चयन आडवाणी का एक चालाक फैसला माना गया। क्योंकि उमा भारती विवाद ज्यादा खड़ा करती थीं और काम कम। यह केवल जनहित के कामों के साथ नहीं है बल्कि वो संघ के एजेंडे को भी ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही थीं। शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तित्व ऐसा है कि

बिना कोई विवाद खड़ा किए, बिना छवि को कट्टर बनाए वो सब कुछ कर जाते हैं, जो आरएसएस चाहता है। शिवराज ने इसको साबित भी किया है।

सनद् रहे कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने 13 सालों के कार्यकाल में मध्यप्रदेश को बहुत शांत तरीके से हिन्दूकरण किया है। वो कहते हैं, आरएसएस के लिए जो काम उमा भारती और बाबूलाल गौर ने भी नहीं किया, उसे शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीनों में ही 2006 में कर दिया था। गांधी जी की हत्या के बाद सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में जाने पर पाबंदी थी, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने खत्म कर दिया। ये बुजुर्गो को मुफ्त में तीर्थयात्रा कराते हैं। शादियां कराते हैं, बाद में भेदभाव के आरोप लगे तो निकाह कराना भी शुरू किया। धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून बनाया। उज्जैन में कुंभ हुआ तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दिगर बात है कि मध्यप्रदेश में इस बात को हर कोई स्वीकार करता है कि दिग्विजय सिंह के 10 सालों के शासनकाल में सड़क और बिजली की हालत बहुत बुरी थी। उस वक्त भोपाल से सागर जाने में उनके छह से सात घंटे लग जाते थे, लेकिन अब अच्छी सड़क होने के बाद मुश्किल से तीन-चार घंटे लगते हैं। वही आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि आधारभूत ढांचे में निवेश होने में सिंचाई सबसे अहम मानी गई। इसके साथ ही अच्छी नीतियां भी बनीं। वही आईजीआईडीआर (इन्कम जेनरेशन एंड इनइक्वालिटी इन इंडियाज एग्रिकल्चर सेक्टर) के 2016 के रिसर्च पेपर के अनुसार 2003 से 2013 के बीच किसानों की आय में 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। जिससे चौहान ने खुद को किसान नेता के रूप में पहचान बनाने में सफलता हासिल कर ली थी।

गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार 13 सालों से ज्यादा वक्त तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने सालों तक मध्यप्रदेश की कमान किसी और के पास नहीं रही। हालांकि 2018 के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व कांग्रेस पर भारी पड़ेगा और बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता में आएगी। इस बात को लगभग सभी लोग मानते हैं कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कद का कांग्रेस में कोई नेता नहीं था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आखिर चौहान कहां चूक गए? वही एक वरिष्ठ पत्रकार का शिवराज के हार के संबंध में मानना है कि मध्यप्रदेश में यह चौहान की चूक नहीं है, बल्कि यह जनादेश केंद्र सरकार की नोटबंदी और गलत नीतियों के खिलाफ है। नतीजे आने के बाद गांव वालों से बात किए जाने पर स्पष्ट था कि कोई शिवराज सिंह चौहान की बुराई नहीं चाहता। उनके हार का कही न कही कारण नोटबंदी रहा है। नोटबंदी से आम लोग प्रभावित हुए हैं और जीएसटी से मध्य वर्ग। दिगर बात है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व के कारण ही बीजेपी को कांग्रेस से भी ज्यादा वोट मिले। हम कह सकते हैं कि यह जनादेश शिवराज के चुनाव में मोदी के खिलाफ है। शिवराज सिंह चौहान के 13 सालों के शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा होता तो दोनों पार्टियों में जीत का फर्क महज पाँच सीटों का नहीं होता। मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी

भी इस बात से सहमत हैं कि लोगों में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उस तरह से नाराजगी नहीं थी, जैसी नाराजगी मोदी सरकार और उसकी नीतियों से थी। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में जनादेश वहां की सरकार के पक्ष या खिलाफ में होता है और यह केंद्र की सरकार के आधार पर नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का कहना है कि यह केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार के खिलाफ भी नहीं है। हमने कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। जहां तक सीटें कम होने की बात है तो हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो हमारी चूक हुई है। मध्यप्रदेश में चुनाव के दौरान लोगों से बात करते हुए शिवराज सिंह के प्रति उनकी सहानुभूति छिपती नहीं थी। लोग उनके मंत्रियों की आलोचना करते थे, केंद्र सरकार की आलोचना करते थे लेकिन चौहान से सहानुभूति जताते थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा में जिस अजनास गांव को गोद लिया है, वहां के सुरेश व्यास भी उन्हीं लोगों में से हैं। वो केंद्र सरकार और अपनी सांसद सुषमा के खिलाफ तो गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से सहानुभूति जताते हुए कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही तो कुछ किया है। सनद् रहे कि अगर जनादेश शिवराज के खिलाफ होता तो बीजेपी बुरी तरह से हारती। शिवराज प्रदेश में काफी लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता में उस तरह से कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि कहा जा सकता है कि बीजेपी में घमंड का बढ़ना भी एक समस्या मानी जा सकती है। एबीवीपी के लोगों ने प्रोफेसर की हत्या कर दी थी। हाल ही में एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोत दी थी। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे शिवराज की छवि एक अप्रभावी शासक के तौर

पर भी बनी। लेकिन इसके साथ ही एक रुपए किलो गेहूं देना और सामूहिक शादियां जैसे प्रोग्राम काफी हिट रहे। मध्यप्रदेश में किसानों पर शिवराज सिंह चौहान के शासन काल में गोलियां चलीं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार बनने के 10 दिन बाद ही कर्ज माफी का वादा कर दिया था। हालांकि किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले चौहान को किसानों ने चुनावी पटकनी दी तो इसका एक कारण ग्रामीण आमदनी का कम होना माना जा सकता है। यह इसलिए अहम है क्योंकि मध्यप्रदेश के 76 फीसदी किसानों के पास बहुत छोटी जोत है और ये ग्रामीण मजदूरी पर निर्भर हैं। हालांकि इन सालों में मध्यप्रदेश औद्योगिक सेक्टर में कुछ नहीं कर पाया। 2003 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान 3।6 फीसदी था, जो 2014 में 3.2 फीसदी हो गया। मानव विकास सूचकांक के मामले में भी मध्यप्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 में 47 है पर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा ही है। अगर शिक्षा की बात करे तो इस मामले में भी मध्यप्रदेश की हालत ठीक नहीं है। एएसईआर के सर्वे के अनुसार, मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में 17 फीसदी बच्चे बुनियादी अक्षरों को भी नहीं पहचान पाते हैं, जबकि 14 फीसदी बच्चों

को बुनियादी अंकगणित का ज्ञान नहीं है। यह तस्वीर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 15 फीसदी और 12 फीसदी है। मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की समस्या भी विकराल है। हालांकि तमाम कारणों के बावजूद माना जाता रहा है कि भारत में चुनाव केवल विकास के मुद्दों पर नहीं होते। जाति और मजहब की चुनावों में अहम भूमिका भी होती है और यह चुनाव भी कोई अलग नहीं है। बीजेपी को जीत दिलाने में आदिवासी और पिछड़ी जाति के वोटों की अहम भूमिका रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद किरार जाति के हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी श्रेणी में आती है। बीजेपी ने पहली बार किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आठ दिसंबर, 2003 से पहले बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री सवर्ण बने थे। जाहिर है बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। इनके द्वारा सामूहिक शादियां कराया जाना, लोगों को काफी रास आया और आदिवासी और दलितों के बीच सरकार की यह योजना काफी लोकप्रिय हुई। बावजूद इन सभी को शिवराज को हार का मुंह देखना पड़ा। इन तमाम घटनाक्रम के बावजूद शिवराज अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और सत्ता से विदाई भी उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई देते हुए ली।

विडम्बना देखिए, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी पांच राज्यों के चुनावी परिणाम में पिछड़ गई तो वही बहुजन समाज पार्टी सुप्रिमो मायावती इस चुनाव के मद्देनजर अच्छे बहुमत का कयास लगायी बैठी थी, किन्तु मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावी नतीजों से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की हसरतों को गहरा झटका लगा है। इन तीनों में से दो राज्यों मध्यप्रदेश और राजस्थान में बसपा चुनावी गठबंधन की कांग्रेस की पेशकश को ठुकरा कर अपने अकेले के बूते चुनावी मैदान में उतरी थीं, जबकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की नवगठित पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन तीनों ही राज्यों में उसे उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी। यही नहीं, तीनों राज्यों में वह न तो सीटों के लिहाज से और न ही प्राप्त वोटों के प्रतिशत के लिहाज से पिछले चुनावों के अपने प्रदर्शन को दोहरा सकीं। राजस्थान में उसे 3.0 फीसदी वोटों के साथ छह सीटें, छत्तीसगढ़ में 4.4 फीसदी चार सीटें और मध्यप्रदेश में 0.9 फीसदी वोटों के साथ दो सीटें हासिल हुई हैं। राजस्थान

और मध्यप्रदेश में यह उसका अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन है, जबकि छत्तीसगढ़ में चार सीटें मिलना उसकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। वैसे तो बसपा का मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वह वोट प्रतिशत के लिहाज से अन्य हिन्दीभाषी राज्यों खासकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे खासी दलित आबादी वाले सूबों में भी उसका ठीक-ठाक जनाधार है। बसपा के बारे में यह जगजाहिर है कि गठबंधन की राजनीति में दूसरी पार्टियों से अपनी शर्तें मनवाने, भरपूर मोलभाव करने और साझेदार दलों से अपने जनाधार के समर्थन की भरपूर कीमत वसूलने में इस पार्टी का कोई सानी नहीं है। इस बार भी उसने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर हुई बातचीत में ऐसा ही किया। बसपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मायावती को लग रहा था कि चुनावी राजनीति के लिहाजा से कांग्रेस इस समय अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। संख्या के लिहाज से वह लोकसभा में तो दयनीय स्थिति में है ही, साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में भी एक-एक करके वह सत्ता से बेदखल हो चुकी है।

बताते चले कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वह पिछले डेढ़ दशक से सत्ता से बाहर है तथा राजस्थान में इस समय वह विपक्ष में है। मायावती इस हकीकत को भी जान रही थीं कि पिछले चार वर्षो के दौरान हर तरफ से लुटी-पिटी कांग्रेस के लिए अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों के चुनाव जीवन-मरण से जुड़े हैं। अगर इन राज्यों में तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भाजपा फिर सत्ता में लौट आती है तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सारी संभावनाएं

लगभग खत्म हो जाएंगी। इसी हकीकत को समझते-बूझते हुए मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बुनी। उन्हें लग रहा था कि यही मौका है जब वह कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा झुकाकर उससे तालमेल या गठबंधन की स्थिति में अपनी पार्टी के लिए अधिकतम सीटें छुड़वा सकती हैं। यही सब सोचकर मायावती ने मध्यप्रदेश की 230 में से 50, राजस्थान की 200 में से 45 तथा छत्तीसगढ़ की 90 में 25 सीटें बसपा के लिए मांगीं। मायावती की यह मांग कांग्रेस के लिए न तो दलीय हितों और न ही व्यावहारिक राजनीतिक के तकाजों के अनुरूप थी, लिहाजा गठबंधन नहीं हो सका। बसपा ने मध्यप्रदेश में 2013 के विधानसभा चुनाव में भी 230 में से 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उस चुनाव में उसके महज चार उम्मीदवार ही जीत सके थे और उसे कुल 06.42 फीसदी वोट मिले थे। इस बार भी बसपा ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। सूबे के रीवा, सतना, दमोह, भिंड, मुरैना आदि जिलों में उसका खासा प्रभाव रहा है। इस बार भी भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और दलित समुदाय में भाजपा के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के चलते अपने मजबूत जनाधार वाले इन जिलों में बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद थी। बसपा की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने चुनाव से कांग्रेस से गठबंधन संबंधी बातचीत टूट जाने के बाद दावा भी किया था। मध्यप्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और बसपा 34 वर्ष के इतिहास में अब तक बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने बूते 30 से 35 सीटें जीतकर सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी। लेकिन उनके इस दावे की चुनाव नतीजों ने हवा निकाल दी। उसके प्रभाव वाले सभी जिलों खासकर विंधय इलाके में रीवा, सतना और दमोह जिले में न सिर्फ उसका सफाया हो गया, बल्कि कांग्रेस को भी भाजपा के मुकाबले करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो गया होता तो इस इलाके में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ता। बसपा ने मध्यप्रदेश वाली कहानी राजस्थान में भी दोहराई और सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बीते कुछ चुनावों में उसका

राज्य के धौलपुर, भरतपुर, दौसा और गंगानगर जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन रहता आया है। जिन सीटों पर वह जीत दर्ज नहीं कर सकी वहां उसने परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाई। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी उसने सीटें तो महज तीन ही जीती थीं लेकिन सात सीटों पर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। राज्य में उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2008 के विधानसभा चुनाव में रहा था जब उसने 7.60 फीसदी वोटों के साथ छह सीटों पर जीत दर्ज की थी। अपने इसी पुराने प्रदर्शन के बूते उसे उम्मीद थी कि इस बार भी वह सत्ता विरोधी लहर और दलित आक्रोश के बूते बेहतर प्रदर्शन कर इतनी सीटें जीत लेगी कि सत्ता की चाबी उसके पास रहे, लेकिन उसका यह मंसूबा पूरा नहीं हो सका। सीटों के लिहाज से वह अपने 2008 के प्रदर्शन से आगे नहीं जा सकी और उसे महज छह सीटों से ही संतोष करना पड़ा। उसके वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट आई और वह महज 3 फीसदी वोट ही हासिल कर सकी। सनद् रहे कि कांग्रेस और बसपा में गठबंधन न हो पाने की एक वजह यह भी थी कि चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी के जनाधार की ताकत और अहमियत का अहसास मायावती इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में तीन संसदीय सीटों गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के उपचुनाव में करा चुकी थीं। गोरखपुर और फूलपुर में बसपा ने समाजवादी पार्टी को तथा कैराना में राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन दिया था। तीनों ही जगह भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव के इन नतीजों ने भी मायावती की मोलभाव करने की क्षमता में इजाफा किया था और वह कांग्रेस से अपनी शर्तें मनवाना चाहती थीं। दरअसल, मायावती का लक्ष्य सिर्फ विधानसभा चुनावों में अधिक से अधिक सीटें लड़ना और जीतना ही नहीं था, बल्कि उनकी निगाहें 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी थीं। वे विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में बनने वाले संभावित व्यापक गठबंधन में भी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी करने की स्थिति में आना चाहती थीं, ताकि चुनाव के बाद अगर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बने तो वे प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोंक सकें। देश की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं की तरह मायावती की भी यह राजनीतिक हसरत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन तीन राज्यों में उन्हें मिले निराशाजनक नतीजों ने उनकी अधूरी हसरतों का अंत कर दिया।

गौरतलब है कि जहां इस चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसमें सभी दल के नेता अपने विजय पताखा फहराने की जद्दोजहद में हर कुछ किया। कोई राम मंदिर में पूजा कर रहा था तो कोई शिव की उपासना में जुटा था। इससे यह तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि चुनाव में हिन्दु और हिन्दुत्व फेक्टर अहम हिस्सा माना जा सकता है और ऐसे में देश की बड़ी पार्टी भाजपा द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ नया न किये जाने से हिन्दु वोटर खासा नाराज दिख रहे हैं। साथ ही साथ एस.सी. एस.टी. एक्ट पर भाजपा की झुकाव ज्यादा होने से सर्वण मतदाता के बीच भी भाजपा को नजरअंदाज किया जाना देखा जा सकता है। नतीजतन, इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम ने भाजपा को बहुत कुछ सिखा दिया है। इस बाबत लोकसभा चुनाव के पूर्व ही सर्वणों को लुभाने के लिए 10 फिसदी आरक्षण देने की बात कह डाली और संसद से यह लगभग पारित भी हो चुका है, भले ही कुछ दल के लोग इसका विरोध कर रहे हो किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा यह लिया गया फैसला अहम माना जा रहा है। क्योंकि इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने सर्वणों को उसके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं की थी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की है। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि 2019 के लोकसभा के फाइनल मैच का एजेंडा भाजपा क्या चुनती है? हिन्दुत्व या विकास।

बहरहाल, तीन हिंदी भाषी राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथों भाजपा की हार सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से तो ये उलट-फेर नहीं हुए। अन्य दो राज्यों तेलंगाना और मिजोरम में तो क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना परचम लहराया, इससे अब लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौती है। 2014 में केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से भाजपा 13 राज्यों की सत्ता में आ चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार चुनाव जीतने की उसकी छवि अब अपना प्रभाव खोती जा रही है। पार्टी के भीतर और बाहर आत्मचिंतन की काफी जरूरत है। क्या भाजपा का कट्टरपंथी हिंदुत्व एजेंडा उल्टा तो नहीं पड़ गया? क्या समावेशी, विकास एजेंडे से हटना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति को अपनाना भाजपा के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में महंगा तो नहीं पड़ेगा? ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर व्वॉय

और भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण का बड़ा चेहरा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को इन चुनावों में पार्टी ने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया था। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यों में 74 रैलियों को संबोधित किया, 26 राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 23, मध्यप्रदेश में 17 और तेलंगाना में 8। इसके उलट, विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 31 और 56 रैलियों को संबोधित किया। पिछले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) को भी आकर्षित करने की कोशिश की है। ये संगठन 1980 के उत्तरार्ध से ही अयोध्या के विवादित रामजन्म भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हैं, उनका मानना है कि इसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था और वहां एक मंदिर था। उन्होंने अयोध्या के सरयू तट पर तीन लाख दीयों को प्रज्ज्वलित करके, 2019 में अर्धकुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया और अपने राज्य में राम की विशाल प्रतिमा बनवाने की घोषणा कर केवल 24 घंटे में रामजन्म भूमि विवाद का हल करने का वचन दिया है। अगर योगी आदित्यनाथ का एजेंडा वीएचपी नेतृत्व को यह साबित करना था कि वो नरेंद्र मोदी का विकल्प हैं और हिंदुत्व के एजेंडा का कहीं गंभीरता से पालन करने की चाहत रखते हैं, तो हाल के चुनावी पराजय से उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। चुनावी पर्यवेक्षकों का मानना है कि पार्टी को ये हार अपने विकास के एजेंडे से हटने की वजह से मिली है। हिंदुत्व का एजेंडा पार्टी

को भारी पड़ा है। हालांकि, संघ परिवार में कुछ लोग इस बात से असहमत होते हुए जोर देते हैं कि वास्तविकता इसके विपरीत है। जिस तरह सरकार की आर्थिक नीतियों से लोगों का मोह भंग हुआ है, उसी तरह मंदिर बनाने की प्रतिबद्धता पर भी इसने लोगों का विश्वास खो दिया है। अगर वीएचपी और आरएसएस को सरकार को चेतावनी देने के लिए सड़क पर आना पड़ा तो इससे क्या संदेश जाएगा?

इससे मतदाता क्या समझेंगे? बीते माह दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली के दौरान हजारों लोग राम मंदिर के शीघ्र निर्माण की मांग करने के लिए इकट्ठा हुए और अब तक ऐसा करने में नाकाम रहने के लिए सरकार की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने 'पहले राम को आसन दो, फिर हमको सुशासन दो' के नारे के साथ मोदी सरकार के विकास एजेंडे पर सीधा हमला किया। जानकार भाजपा और संघ-वीएचपी के बीच इस मनमुटाव को पारिवारिक झगड़ा बताते हैं। वे 2001 के उस झगड़े की याद दिलाते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वीएचपी की मांग के अनुसार राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया तो विश्व हिंदू परिषद ने मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी थी। दिगर बात है कि इस बार भाजपा के बहुमत वाली सरकार है, जिसकी चुनौती कमजोर अर्थव्यवस्था है। अब जबकि इन चुनावों में हिंदुत्व के एजेंडे की संभावित नाकामी दिख रही है तो मोदी सरकार के सामने हिंदुत्व और विकास में से

किसी एक को रणनीति के रूप में अपनाने की चुनौती है। संघ अपने अनुशासित कार्यकर्ताओं और पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को जुटाने की काबिलियत के लिए मशहूर है, लिहाजा आम चुनाव में भाजपा की चुनावी सफलता के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। दरअसल, 2014 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में उनकी बदौलत ही भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। यह स्पष्ट है कि उनकी अनदेखी या उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जबकि हिंदुत्व के एजेंडे ने काम नहीं किया तो उदारवादियों ने सरकार से अर्थव्यवस्था पर फिर से ध्यान देने की मांग की है, लेकिन भाजपा में भीतरखाने से राम मंदिर, समान नागरिक संहिता और गौरक्षा के मूल एजेंडे पर बहुत गंभीर होकर वापसी करने की आवाज उठ रही है, ताकि लोगों को लगे कि पार्टी ने इनका त्याग नहीं किया है और इसकी बदौलत अपना आधार मजबूत किया जा सके। यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था का सामना उलटा बयार से हो रहा है, भाजपा-संघ-वीएचपी के भीतर लोग दावा करते दिख रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा ही ज्यादा प्रासंगिक है और वो यह विश्वास भी जताते हैं कि लोकसभा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, किन्तु सच्चाई क्या है यह भविष्य के गर्भ में है और इंतजार है तो आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव का....।

During Crucial Rafale Negotiations, PMO Compromised Defence Ministry's Position

In December 2015, when negotiations were still at a delicate stage, defence ministry file notings have indicated that there was interference from the PMO.

M.K. Venu

In what could trigger yet another political storm over the Rafale controversy, fresh facts have surfaced with regard to the procedures adopted by the Narendra Modi government while clearing the purchase of 36 aircraft. Highly placed sources have confirmed to The Wire that it is officially recorded in government files that the Prime Minister's Office (PMO) was compromising the negotiating position of the defence ministry, which by the end of 2015 was discussing various sensitive aspects of the deal.

What is significant is that the PMO is named in the internal memos as causing problems to the negotiating position of the defence ministry team. As per procedure, the defence ministry's contract negotiation committee has experts who make a completely independent assessment of the purchase of defence equipment. The committee's decisions and assessments are then sent to the Cabinet Committee on Security (CCS). But here, there are indications that the PMO was trying to make premature interventions. It is unlikely that these file notings, made by defence ministry officials, were placed before the Supreme Court. However, it is possible that the Comptroller and Auditor General (CAG) may have accessed these files. The national auditor is yet to finalise its own report on the Rafale deal. The Wire has learned that while the CAG draft report has raised questions over procedures adopted in executing the aircraft deal, it has steered clear of the pricing controversy and has at this stage made no assessment of the offset contracts given to the private sector. Sources said the defence ministry's negotiating team, which works under the overall supervision of the Raksha Mantri – Manohar Parrikar, at the

time – had reached a critical stage of negotiations for the 36 Rafale aircraft by December 2015.

It may be recalled that after Modi abruptly announced the new deal in France on April 10, 2015, the Defence Acquisition Council headed by Manohar Parrikar formally approved the 'Acceptance of Necessity for buying the jets in May 2015. In the subsequent six months, the actual negotiations had gathered pace. By December 2015, the negotiations were poised very delicately and the law ministry had noted that a sovereign guarantee from France for the future performance of the Rafale contract was a necessary condition for a government-to-government deal. Not surprisingly it was in the same month – December 2015 – that the defence ministry officially noted that the PMO was compromising its negotiating position. It seemed that the PMO was interfering at this stage. And this got recorded in an internal memo, according to one highly-placed source with knowledge of the matter. Then in January 2016, the contract negotiation committee finalised all aspects of the new deal except that the financial terms – the most tricky aspect – was put off by a few months. Finally, the controversial deal was fully finalised and taken to the Cabinet Committee for Security for clearance in August 2016. There was obviously some resistance from the defence ministry negotiation team to various aspects at various stages. It is learnt that the increased benchmark price of 36 Rafale jet aircraft – from 5.2 billon euros to 8.2 billion euros – was resisted by many members of the team before being sent to the the CCS. The defence minister at the time neither put his signature on the increased price nor did he sign off on diluting the sovereign guarantee to a mere letter of comfort.

कश्मीर में सत्ता सबको चाहिए लोकतंत्र किसी को नहीं

अब इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कश्मीर का मसला अपनी विकृति की चरम अवस्था में पहुंच गया है। मौजूदा सरकार, शासक दल और राज्यपाल के साथ ही सूबे की राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम राजनीतिक दलों के तेवरों को देखते हुए इस स्थिति का कोई तुरत–फुरत हल दिखाई नहीं देता। केंद्र सरकार ने पिछले साढे चार वर्षों के दौरान कश्मीर को लेकर जितने भी प्रयोग किए है, उससे तो मसला सुलझने के बजाय इतना ज्यादा उलझ गया है कि कश्मीर अब देश के लिए समस्या नहीं रहा बल्कि एक गंभीर प्रश्न बन गया है। वैसे यह प्रश्न बीज रूप में तो हमेशा ही मौजूद रहा लेकिन इसे विकसित करने का श्रेय उन नीतियों और फैसलों को है, जो अंध राष्ट्रवाद और संकुचित लोकतंत्र की देन हैं। इस सिलसिले में केंद्र में अलग–अलग समय पर रहीं अलग–अलग रंग की सरकारें ही नहीं, बल्कि सूबाई सरकारें भी बराबर की जिम्मेदार रही हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले और लंबे समय से आतंकवाद तथा अलगाववाद के शिकार इस सूबे की बदनसीबी यह भी है कि देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक वह वास्तविक लोकतंत्र से लगभग महरूम ही रहा। इस समय भी वहां पिछले करीब चार महीने से कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। जो थोडी–बहुत संभावना थी और सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे थे, उस पर सूबे के राज्यपाल ने विधानसभा भंग करके पानी फेर दिया है। राज्यपाल के फैसले की व्यापक तौर पर आलोचना हो रही है। आलोचना करने वालों में सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां–नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) भी शामिल हैं। इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया। इस सिलसिले में राज्यपाल की ओर से जो सफाई और दलीलें दी जा रही हैं वे निश्चित बेदम हैं, लेकिन कुछ सवाल नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के नेताओं से भी पूछे जाने चाहिए। सबसे अहम सवाल है कि जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर वे राज्यपाल को कोस रहे हैं, उस लोकतंत्र में उनका कितना यकीन है? जम्मू–कश्मीर में पिछले महीने नगरीय निकायों के चुनाव हुए और इस समय पंचायत चुनाव का दौर जारी है। सूबे में निचले स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिए यह चुनाव करीब 13 साल बाद हो रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र की आत्मा कहा और माना जाता है, लेकिन विधानसभा भंग किए जाने को लोकतंत्र की हत्या बता रही दोनों ही पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने इन चुनावों का बिना किसी जायज वजह के बहिष्कार किया। पहले इस फैसले का एलान नेशनल कांफ्रेंस के नेता डॉ. फारुक अब्दुल्ला ने किया और फिर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने। दोनों नेताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35ए पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, लिहाजा उनकी पार्टी इन चुनावों में शिरकत नहीं करेगी।

गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35ए जम्मू–कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की शक्ति देता है। यह सही है कि केंद्र में सत्तारूढ भाजपा अनुच्छेद 35ए और जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ रही है, मगर उसकी अगुवाई वाली केंद्र

सरकार ने इस मसले पर कभी भी अपना औपचारिक और स्पष्ट नजरिया जाहिर नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस अलग–अलग समय में भाजपा के साथ केंद्र और सूबे की सत्ता में साझेदार रह चुकी हैं। इसलिए अब इस मुद्दे पर उनका भाजपा और केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहना और इस बहाने स्थानीय चुनावों का बहिष्कार करना बेमानी है। यह कोई ऐसी वजह नहीं थी कि सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों का बहिष्कार करतीं, लेकिन दोनों ने ऐसा ही किया। घाटी में सक्रिय अलगाववादी समूहों ने भी हमेशा की तरह इस बार इन चुनावों के भी बहिष्कार का फैसला किया। आतंकवादियों की ओर से भी धमकी भरे फरमान के जरिये लोगों से कहा गया कि वे इन चुनावों से दूर रहें। कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों ने चुनाव से अलग रहकर प्रकारांतर से अलगाववादियों और आतंकवादियों की हौसला अफजाई ही की। नतीजा यह हुआ कि नगरीय निकाय चुनाव एक तरह से मजाक बनकर रह गए। जम्मू इलाके में तो फिर भी लोग मतदान के लिए घरों से निकले और वहां 55 से लेकर 60 फीसदी मतदान हुआ, लेकिन लेह–लद्दाख और घाटी के इलाकों में महज 9 से 10 फीसदी तक ही मतदान हुआ। इस प्रकार करीब 35 फीसदी ही कुल मतदान हो सका। पंचायत चुनावों का अभी पहला दौर संपन्न हुआ है और उसमें भी मतदान की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। बाकी के तीन चरणों में भी संभवतया यही स्थिति रहेगी। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू–कश्मीर में करीब 72 फीसद और 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में करीब 70 फीसद मतदान हुआ था। दोनों ही चुनावों में लोगों ने अलगाववादियों की अपील और आतंकवादियों की धमकियों को नजरअंदाज कर चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था जताई थी। जाहिर है कि इन चुनावों से पहले और इन चुनावों के वक्त सूबे में हालात काफी हद तक सामान्य थे। आतंकवादी वारदातों में कमी आ गई थी और पर्यटकों की आमद भी खासी हो रही थी। लेकिन राज्य में नई निर्वाचित सरकार बनने के बाद हालात फिर बदलने यानी बिगडने लगे। असंतोष और अलगाव की आवाजें फिर तेज हो गईं और आतंकवादी हिंसा की वारदातों में भी लगातार इजाफा होता गया। इस बदली हुई स्थिति के लिए मोटे तौर पर केंद्र और सूबे की सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस सूबे की प्रमुख पार्टियां हैं, इस नाते दोनों की जिम्मेदारी थी कि वे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में शामिल होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये घाटी में हालात सामान्य बनाने तथा अलगाववादियों को अलग– थलग करने में अपनी भूमिका निभातीं, लेकिन दोनों ने बेजा बहानेबाजी कर चुनाव का बहिष्कार किया। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ निचले स्तर पर लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया को कमजोर किया बल्कि जाने–अनजाने अलगाववादियों को भी ताकत पहुंचाने का काम किया। इस सिलसिले में राज्यपाल की भूमिका भी कम विवादास्पद नहीं रही। बेहतर होता कि वे स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का फैसला करने से पहले राज्य के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की दिशा में पहलकदमी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल के बजाय निर्वाचित सरकार की तरह काम करते हुए राज्यपाल शासन लागू होते ही मनमाने ढंग से चुनाव की घोषणा कर दी और अभी भी वे पिलपिली दलीलों के साथ जिस तरह विधानसभा भंग करने के अपने फैसले का औचित्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि लोकतंत्र में उनका भी उतना ही यकीन है, जितना चुनाव का बहिष्कार करने वाली पार्टियों का।

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कश्मीर हमारे राजनीतिक दलों और शासक वर्ग के हाथों का खिलौना बना हुआ है। बारहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और इतिहासकार कल्हण ने अपने रचित प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिणी में कहा है– कश्मीर पर बल द्वारा नहीं, केवल पुण्य द्वारा ही विजय पाई जा सकती है। यहां के निवासी केवल परलोक से भयभीत होते हैं, न कि शस्त्रधारियों से।' कल्हण की यह बात कश्मीर की ताजा स्थिति के संदर्भ में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। हकीकत यही है कि भारत की आजादी और भारतीय संघ में कश्मीर के विलय के बाद से ही कश्मीर लगातार बल और छल का शिकार होता रहा है– कभी कम तो कभी ज्यादा। यही वजह है कि कश्मीरी अवाम भी हमेशा दिल्ली के शासकों को और यहां तक कि शेष भारत को भी शक की नजर से देखता रहा है, भले ही हम मौके–बेमौके यह दोहराते रहे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज तो कश्मीरी अवाम इतना क्षुब्ध और बेचैन है कि वह भारत के साथ रहना ही नहीं चाहता।

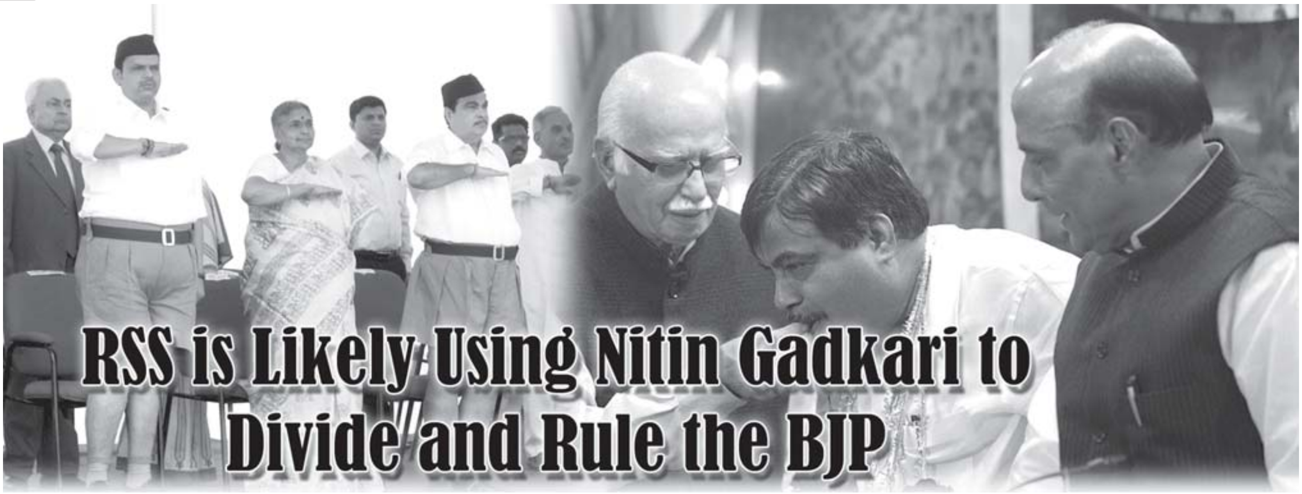

RSS is Likely Using Nitin Gadkari to Divide and Rule the BJP

The Union minister's seeming rebellion, protestations notwithstanding, sends out the message that this time Modi is truly on his own.

Sujata Anandan

Union minister Nitin Gadkari is hopping mad at the media.

"The media is left with absolutely no integrity," he told this correspondent last week while flatly denying he had said any of the things attributed to him in the past couple of weeks. "They put words in my mouth over my Pune speech [wherein he is supposed to have said 'success has many fathers and failure is an orphan']. And my Delhi address was taken out of context [he was reported as saying 'if he were party president, he would have to be held responsible for the bad performance of his MPs and MLAs']." Be that as it may, those comments are now being interpreted as the bugle of revolt against Narendra Modi and Amit Shah – not just by political rivals or the media but also by a whole section of the BJP, who adore Gadkari from his days as party president. They are chafing at the tight grip of the Modi-Shah duo on the party and their refusal to allow any party man room for basic dissent or even simple disagreement. Gadkari may be protesting too much. He could not have made those comments without the backing of the top brass of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the confidence that they would back him up in the event of a fallout with the party leadership. Although the minister is wary of being

asked if he is bidding for the prime minister's post in 2019, Dilip Deodhar, an RSS ideologue, told this correspondent he has warned Gadkari that his caste (Brahmin) is all wrong for the job of prime minister. "The RSS still needs an OBC to weave the larger community of Hindus together at the next elections and Modi continues to be their best bet in this regard." Even so, sources say recent events have shown that Modi may not have the complete backing of the RSS, whose leadership has been upset at his dictatorial, winner-takes-all style. Mohan Bhagwat had warned recently that the Sangh will not support any particular party in the next elections. "Since its inception, RSS has kept itself aloof from the party politics and the politics influenced by castes and creeds and will continue to do so," the RSS chief said.

The leadership

may be using the more-amenable Gadkari – a Nagpur politician whose proximity to the RSS is well-known – to divide and rule the BJP. During the recent elections to the Hindi heartland states, the party did not have the full support of the pracharaks as it did in 2014. The BJP's defeat in these states is being attributed to the withdrawal of that support and Gadkari's statements are now seen by pracharaks on the ground as confirmation and reaffirmation of Mohan Bhagwat's earlier statement that the RSS will not work for any political party in 2019. Gadkari's seeming rebellion, his protestations notwithstanding, now reinforces that fact but also sends out the message that this time Modi is truly on his own. However, the pracharaks can nonetheless look to Gadkari and the RSS to pick and choose the candidates they will work for and ensure their victories. According to one such pracharak, there is a feeling within not just the RSS top brass but also among its grassroots workers that the Modi-Shah duo has unduly cashed in on their hard work and never acknowledged anyone else's contribution, taking all the credit for themselves. Perhaps that is why the comment that party leaders should learn to accept failures as well as successes. When the RSS supported Modi in 2014, even they did not believe the BJP could reach an absolute majority on its own. " We had thought 210-230 (seats) at the most, the rest would come from allies," said one RSS ideologue. This time they will be happy to settle for less than 200 for only the drastically reduced majority will cut Modi down to size and help the RSS contain their high-flying pracharak-turned-most inaccessible prime minister of all times – a man who has been not just trying to rid India of the Congress but also, subtly, of the RSS even if he is in tune with their ideology. Gadkari is very important to those plans for he is an amiable, amenable man, networked with many other political parties and an old-fashioned politician who does not believe political rivals should be sworn enemies. He is said to be building bridges with many opposition parties, including former NDA and UPA allies, for just such an eventuality in 2019.

With Sushma Swaraj ostensibly out of the race, Arun Jaitley unlikely to win a popular election, L.K. Advani too old for the office (in any case neither of them is popular with the RSS) and Manohar Parrikar, another RSS favourite, seriously ailing, the Sangh is left with only two options – Rajnath Singh and Nitin Gadkari– who they can trust to head the parliamentary party in 2019 and not get above themselves as Modi-Shah have done.

However, with Gadkari denying he ever said the things attributed to him, where does that leave things for Modi and Shah? Continuing to be suspicious of both the RSS and its blue-eyed boy, Modi has not been on talking terms with Gadkari for months now and Shah treats the former president of the BJP little better than an ordinary party worker. That relations between the two sides are at rock bottom is one of the worst-kept secrets in political circles. If Gadkari is resentful, he has not let it show and even after making these remarks, which have shown him as a potential rebel, he has tried his best to smoothen things in public. His supporters privately claim that the Modi-Shah combine will work to get Gadkari defeated in Nagpur, thus finishing off the possible threat after the elections. It may be somewhat fanciful, but it indicates the deepening mistrust in the Gadkari camp. The rift between the two sides – Modi-Shah on one and Gadkari, possibly backed by the RSS on the other – is now a reality. Whether Gadkari has the strength, the heft or the willingness to stand up to the duo remains to be seen.

बोगीबील ब्रीज निर्माण से सहमा चीन

● अमित कुमार/प्रदीप कु सिन्हा

एशियाई देशों में भारत देश एक बड़ी शक्ति के साथ सामने आ रहा है, जिसके हलक से भारत के पड़ोसी देशों में हलकान मचे हैं और इसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। खासतौर पर भारत के साथ पूर्व में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और कुटनीति में हासिल चीन से युद्ध हो चुका है तथा इसमें भारत की हार हुई थी। इस बाबत सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान से ज्यादा चीन को गंभीरता से लिया जाना देश के प्रधान के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन ने कहा था कि भारत और चीन के बीच मतभेद गहराने की संभावना है और डोकलाम गतिरोध के मामले में कहा जाना की बस एक बार हो गई, जैसी कोई घटना नहीं है तथा चीन का ध्यान पूर्व से लद्दाख की तरफ चला गया है। सनद् रहे कि चीन आर्थिक एवं सीमा मुद्दों पर मतभेदों के अलावा आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत द्वारा समर्थन करने से कुपित हैं। चीन, भारत के पड़ोसियों के साथ मित्रता कर और भारत को मित्रविहीन बनाकर उसे वश में करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही भारत के पड़ोसियों को अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक ब्लैकमेल समेत कई तरीके अपनाए हैं। उसने नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के साथ यही तरीके अपनाया। ध्यान रहे कि चीन द्वारा श्रीलंका में हम्बानटोटा बंदरगाह का हाथ में लेना, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और अफ्रीका के दिजबोती में नौसेना अड्डा बनाना तथा ऐसी उपस्थिति बढ़ाने की उसकी मंशा से दोनों विशाल एशियाई देशों में संबंध बिगड़ेंगे ही। ऐसे में भारत को अपने सटे सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी नजर रखना होगा। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के सपने को साकार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर लंबा बोगीबील पुल का निर्माण करवाकर चीन को औकात में रहने की चुनौती दे डाली है।

बताते चले कि एशिया के दूसरे सबसे लंबे रेल-सड़क पुल बोगीबील की मियाद कम से कम 120 साल है। इसके बारे में मुख्य अभियंता मोहिंदर सिंह द्वारा बताया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 4.9 किलोमीटर लंबा पुल देश का पहला पूर्ण रूप से जुड़ा पुल है और पूरी तरह से जुड़े पुल का रख-रखाव काफी सस्ता होता है। इस पुल के निर्माण में 5900 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इससे असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा दूरी घट कर 4 घंटे रह जाएगी। इसके अलावा दिल्ली से डिबरूगढ़ रेल यात्रा समय 3 घंटे घटकर 34 घंटे रह जाएगा। इससे पहले यह दूरी 37 घंटे में तय होती थी। यह 4.94 किलोमीटर लंबा रेल/रोड ब्रिज भारत को नई ताकत देने वाला है। खासकर अरुणाचल सीमा से सटे होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय रेल के इस पुल की आधारशिला साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और 2007 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया, लेकिन पिछले 4-5 साल से इसके निर्माण को खास तेजी दिखाई गई थी। किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे गंभीरता से लेकर इसका निर्माण पूरा कर दिया और बीते 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के जन्मदिन पर इस ब्रीज का उद्घाटन कर देशवासियों को नये साल का तोहफा दिया है। सनद् रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में बनी 4.94 किलोमीटर लंबी और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यह परियोजना न केवल आम लोगों के

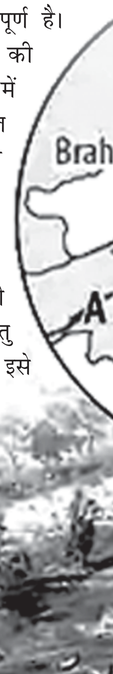

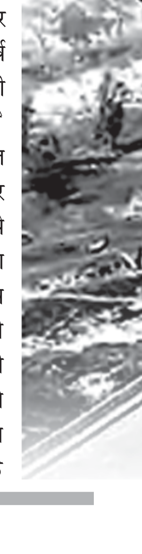

लिए अपितु, रक्षा मोर्चे पर भी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गई है। यह बोगीबील पुल, असम समझौते का हिस्सा रहा है और इसे 1997-98 में अनुशंसित किया गया था। आपको बता दें कि यह पुल अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर रक्षा सेवाओं के लिए भी आड़े वक्त में खास भूमिका निभा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 22 जनवरी, 1997 को इस पुल की आधारशिला रखी थी, लेकिन इस पर काम 21 अप्रैल, 2002 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हो सका।

गौरतलब है कि परियोजना में अत्यधिक देरी के कारण इसकी लागत में 85 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई। शुरुआत में इसकी लागत 3230.02 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 5,960 करोड़ रुपये हो गई। इस बीच पुल की लंबाई भी पहले की निर्धारित 4.31 किलोमीटर से बढ़ाकर 4.94 किलोमीटर कर दी गई। परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पुल के निर्माण को 2007 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस कदम के बाद से धन की उपलब्धता बढ़ गई और काम की गति में तेजी आ गई। अधिकारियों ने इस पुल के बारे में कहा, यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर रहने वाले लोगों को होने वाली असुविधाओं को काफी हद तक कम कर देगा पर इसकी संरचना और इसकी डिजाइन को मंजूरी देते समय रक्षा आवश्यकताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक रक्षा सूत्र ने कहा है कि यह पुल सुरक्षा बलों और उनके उपकरणों के तेजी से आवागमन की सुविधा प्रदान करके पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि आपात स्थिति में एक लड़ाकू विमान भी इस पर उतर सके। लिहाजा, पुल का सबसे बड़ा लाभ दक्षिणी से उत्तरी तट तक सैनिकों की आसान आवाजाही में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चीन की तरफ, भारत की सीमा में कई सौ किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पहले ढ़ोला-सदिया पुल और अब बोगीबील- ये दोनों भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रणव ज्योति शर्मा ने कहा है कि चीन के साथ भारत की 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है और यह पुल भारतीय सेना के लिए सीमा तक आवागमन में मदद करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल असम में डिबरूगढ़ शहर से 17 किमी दूर स्थित है और इसका निर्माण तीन लेन की सड़कों और दोहरे ब्रॉड गेज ट्रैक के साथ किया गया है। यह पुल देश के पूर्वोत्तर इलाके की जीवन रेखा होगा और असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल यहां से 450 किलीमीटर दूर गुवाहाटी में ही ब्रह्मपुत्र को पार करने के लिए नदी पर पुल मौजूद है, जबकि सड़क पुल भी यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर है। इस बाबत अरुणाचल प्रदेश के अंजाव, चंगलांग, लोहित, निचली दिबांग घाटी, दिबांग घाटी और तिरप के दूरस्थ जिलों को इससे बहुत लाभ होगा।

ध्यान रहे कि इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो उन्हें यहां मार्च से लेकर अक्टूबर तक होने वाली बारिश के बाद ही काम करने का समय मिला है। इसके अलावा नदी के पानी के भारी दबाव में होने के नाते किसी भी तरफ से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है और कहीं भी टापू बन जाता है ऐसे में काम करना या फिर लोकेशन बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सबसे निबटकर पहली बार रेलवे ने स्टील गर्डर का इस्तेमाल कर इतना बड़ा पुल बनाया है। इस पुल में कहीं भी रिपीट नहीं लगाया गया बल्कि हर जगह लोहे को वेल्ड किया गया है जिससे इसका वजन 20% तक कम हो गया और इससे लागत में भी कमी आयी है। बेहतरीन प्रदर्शन की एक झलक है।

सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या विस्फोट

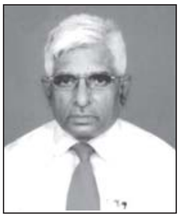

● ललन कुमार प्रसाद

वर्ष 1804 में दुनियां की आबादी 100 करोड़ थी, जिसे अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार पूरा होने में दो लाख वर्ष लगे थें। दरअसल 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के बाद आबादी में वृद्धि हुई और साथ में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ा। परिणाम महज अगले 130 साल यानि साल 1934 में आबादी 200 करोड़, फिर अगले 33 साल यानि 1967 में आबादी 300 करोड़, फिर अगले 14 साल यानि 1981 में आबादी 400 करोड़ और फिर अगले 37 साल यानि 2018 में आबादी 736 करोड़। साल 2018 में दुनियां की कुल आबादी का 58 फिसदी यानि 440 करोड़ सिर्फ दस देशों में निवास करते हैं, शेष 43 फिसदी यानि 323 करोड़ 223 देशों में रहते हैं। बात यह है कि धरती पर मनुष्य की आबादी चक्रवृद्धि अनुपात में हर साल 1.1 फिसदी की दर से बढ़ रही है। यदि आगे भी इसी अनुपात में बढ़ती रही तो साल 2030 में मध्य तक 8.6 अरब, साल 2050 तक 9.8 अरब और 2100 तक 11.2 अरब हो जाने का अनुमान है। बढ़ती आबादी के चलते 2050 में जब दुनियां की आबादी 9.8 अरब हो जायेगी तो उस समय खाद पदार्थो की मांग आज की तुलना में दोगुनी हो जायेगी। साथ ही दुनियां का हर छठ्ठा व्यक्ति भारतीय होगा। ऐसा इसलिए कि वर्तमान में भारत की आबादी 1.11 फिसदी की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जो चीन की तुलना में करीब तीन गुना अधिक है। दुनियां में पिछले वर्ष सबसे अधिक आबादी भारत की बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत 2025 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनियां का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा। वर्ष 2018 में चीन की आबादी 141 करोड़ थी और भारत की आबादी 135 करोड़। विगत् वर्ष चीन की आबादी में 55 लाख की वृद्धि हुई, जबकि भारत में 1 करोड़ 48 लाख। पिछले वर्ष आबादी में चीन की वृद्धि दर 0.39 फिसदी रही और भारत की 1.11 फिसदी। बिहार का प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्तमान में चीन में प्रति वर्ग किलोमीटर में 151 लोग रहते हैं और भारत में प्रतिवर्ग किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं। चीन में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 6 लाख 90 हजार रूपये हैं और भारत में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 1 लाख 40 हजार रूपये हैं। वर्तमान में भारत की आबादी 135 करोड़ 40 लाख 52 हजार है। कहने को भारत एक देश है, पर यहां की

आबादी 29 देशों के बराबर है। झारखण्ड राज्य की आबादी सउदी अरब के बराबर है। जबकि झारखण्ड से सउदी अरब 27 गुना बड़ा देश है। बिहार राज्य की आबादी इथोपिया के बराबर है, जबकि बिहार से इथोपिया 12 गुना बड़ा देश है। पिछले साल सबसे अधिक आबादी 1 करोड़ 48 लाख भारत की बढ़ी है। युनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड (युनिसेफ) के मुताबिक नववर्ष के पहले दिन मंगलवार दिनांक 1 जनवरी 2019 को दुनियां भर में करीब 3 लाख 95 हजार बच्चों का जन्म हुआ। इनमें सबसे अधिक लगभग 70 हजार बच्चे भारत में पैदा हुए। अर्थात नववर्ष के पहले दिन सबसे अधिक बच्चे भारत में जन्में।

✯ **भारत के कुछ प्रमुख सबसे आबादी वाले शहर :-** समान्यतः शहरों में रोजगार, नौकरी आदि के साथ-साथ जनसुविधाएं, जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, आवागमन के साधन सर्वाधिक है। यही कारण है कि लोग गांव से कस्बा, कस्बा से शहर और शहर से नहर की ओर पलायन कर रहे हैं। नतीजा किसी भी देश में अधिक से अधिक लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। मसलन जापान की राजधानी टोकियो दुनियां का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। फिलहाल टोकियो की आबादी लगभग 3 करोड़ 70 लाख है। दूसरे नंबर पर चीन का संघाई शहर आता है, जहां की आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख है। भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई तीसरे नंबर पर आती है, जहां की आबादी लगभग 2 करोड़ 32 लाख है। पिछले दस वर्षों में सिर्फ झारखण्ड में 3 लाख 83 हजार से अधिक लोग गांव छोड़ चुके हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड राज्य में विरान हो चुके गांव की संख्या 968 से बढ़कर 1668 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक आज दुनियां की लगभग 55 फिसदी आबादी शहरों में रहती है। नवीनत्तम अनुमानों के मुताबिक भारत की 32.37 फिसदी आबादी शहरों में रहती है, जो शहरों में रहने वाली दुनियां की सबसे बड़ी आबादी है। यदि गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं रोका गया तो 2030 तक भारत में शहरों की आबादी 40 फिसदी से भी अधिक हो जायेगी, जिससे ढ़ेर सारी नई-नई समस्याएं

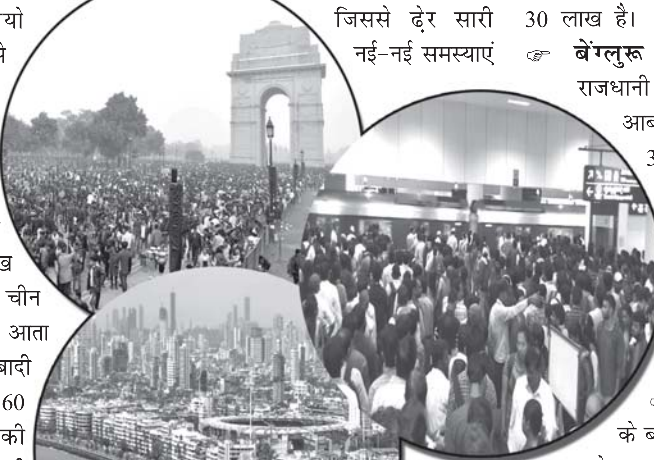

जैसे-रोजगार, नौकरी आदि की समस्या भयावह हो जायेगी और जनसुविधाएं जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने की पानी की समस्या बद से बद्तर हो जायेगी।

✯ **देश की कुछ प्रमुख सबसे आबादी वाले शहर है :-**

☞ **मुम्बई :-** महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जहां की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ 32 लाख है। इसे भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। मुम्बई की फिल्म इंडस्ट्रीज (बॉलीबूड) पूरी दुनियां के फिल्म जगत में विशेष स्थान रखती है।

☞ **दिल्ली :-** भारत की राजधानी दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ 30 लाख है।

☞ **बेंग्लुरू :-** कर्नाटक की राजधानी बेंग्लुरू की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख है। बेंग्लुरू को भारत का आई.टी. हब कहा जाता है, क्योंकि देश की सर्वाधिक प्रमुख आई.टी. कंपनियां यही अवस्थित है।

☞ **पूणे :-** मुम्बई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे प्रमुख शहर पूणे है। जहां की आबादी 1 करोड़ के पार है। इस शहर में फिल्म एण्ड टेलीविजन संस्थान अवस्थित है, जो फिल्म जगत से जुड़े विषयों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु देश का सबसे बड़ा संस्थान है।

☞ **चेन्नई :-** तमिलनाडू की राजधानी चेन्नई की आबादी लगभग 1 करोड़ है।

☞ **हैदराबाद :-** आंध्र-प्रदेश और तेलांगना की राजधानी हैदराबाद की कुल आबादी 95 लाख है। यहां का सलारजंग म्युजियम विश्व-विख्यात है। विश्व प्रसिद्ध हीरे का खान गोलकुंडा हैदराबाद के समीप ही स्थित है।

☞ **अहमदाबाद :-** गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की आबादी लगभग 60 लाख 50 हजार है।

☞ **सूरत :-** गुजरात का दूसरा सबसे प्रमुख शहर सूरत है। जहां की आबादी लगभग 60 लाख है। यह शहर दुनियां भर में कपड़ा और हीरा के कारोबार के लिए मशहूर है। पूरी दुनियां में इन दोनो पदार्थो का सर्वाधिक उत्पादन इसी शहर में होता है।

✯ **आबादी बढ़ने के कारण :-**

☞ आबादी बढ़ने में सबसे अहम कारण निरक्षरता है। निरक्षरता के कारण ही देश की एक बड़ी आबादी बच्चे पैदा करती रहती है। ऐसा इसलिए की 'छोटा परिवार-सुखी परिवार' उन्हें समझ में नहीं आता। अर्थात् जनसंख्या विस्फोट के मूल में

नववर्ष के पहले दिन टॉप 4 आबादी ग्रोथ वाले देश

देश	-	बच्चों की संख्या
भारत	–	69944
चीन	–	44940
नाइजीरिया	–	25685
पाकिस्तान	–	15112

है करोड़ों लोगों का अनपढ़ होना।
☞ हमारे देश में प्रजनन दर दूसरे देशों के मुकाबले अधिक है। हमारे देश में जन्म का दर मृत्यु दर से अधिक है।
☞ लचर सरकारी व्यवस्था तथा परिवार नियोजन में लगे अधिकांश सरकारी मुलाजिमों की अक्रमण्यता के चलते जनसंख्या नियंत्रण हेतु उठाये गये कदमों को जनता गंभीरता से अमल नहीं करती। यही कारण है कि परिवार नियोजन के तरीके जैसे गर्भ-निरोधक दवाओं का सेवन, पुरूष नसबंधी, महिलाओं द्वारा कॉपर ट्यूब इस्तेमाल आदि पर्याप्त असरदार साबित नहीं हो रहे हैं।
☞ भारी संख्या में शरणार्थियों का देश मं आना और पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के ममता जैसे मुख्यमंत्री राजनेताओं द्वारा उन्हें देश में भारत की नागरिकता दिलवाकर स्थायी रूप से बसा लेना। वर्ष 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा चम्पारण में मोतिहारी के निकट जीवधारा के पास लाखों पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में स्थायी रूप से बसा लिया गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा बंग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दिलवाकर भारत में ही स्थायी रूप स बसा लिया गया है। इस कड़ी से कुछ और राजनेता जुड़े हुए हैं, जैसे-पश्चिम बंगाल में सीपीएम के पूर्व मुख्यमंत्री और असम में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री। असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर स्थायी रूप से बसा लिया गया है। आश्चर्य की बात है कि देश की एक-एक इंच जमीन भारतीय जनता का है, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू, ममता बनर्जी जैसे नेतागण जनता की जमीन को अपनी जागीर मानते हैं। इसलिए बंग्लादेशियों, रोहिंग्यों आदि को भारत की नागरिकता प्रदान करवाकर भारत में ही बसा लेते हैं, जबकि इन राजनेताओं का कर्तव्य है, देश की एक-एक इंच जमीन की हिफाजत करना। इसी के लिए भारतीय जनता ने देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब पांच करोड़ बाग्लादेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, जो देश के ढ़ेर सारे शहरों में देखे जा सकते हैं। ये बाग्लादेशी चोरी, डकैती, हत्या जैसे आपराधिक कार्यों में लिप्त हैं। मसलन दिल्ली के कई इलाकों में इनका आतंक है। ये मूल भारतीयों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। भारतीय जनता के पैसों पर ऐशो-आराम की जिंदगी बसर करने वाले राजनेता गद्दारी का शानदार नमूना पेश कर रहे हैं। इन देशदोही

राजनेताओं को अधिकांश सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थ में अंधा होकर भरपूर साथ दे रहे हैं, तभी तो इन बंग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। फिर ये बंग्लादेशी भारतीय नागरिक अपनी संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हेतु अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। इन बंग्लादेशी नागरिकों की गतिविधियां देश की आजादी के लिए खतरे की घंटी है। वैसे ही हमारा देश आबादी के बोझ तले दबा हुआ है और उपर से कई करोड़ घुंसपैठिएं बंग्लादेशियों तथा रोहिंग्यों के बोझ।
☞ समाज के सभी वर्गों में परिवार नियोजन के प्रति घर लापरवाही यानि जागरूकता का जर्बदस्त आभाव। लोगों के बीच रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन सहित अन्य जनसुविधाओं की बढ़ रही प्रचंड चुनौतियों के प्रति उदासीनता।

✯ जनसंख्या विस्फोट का असर:-

☞ **जनसंख्या विस्फोट की उपज है दड़बा संस्कृति :-** पहले दालान, बरामदा, अटारी (घर का ऊपरी कमरा), आंगन, अनाज रखने के लिए घर के आंगन में बनी माटी की कोठी या फिर दुआर यानि घर के दरवाजे के बाहर कुछ हटकर खाली जमीन पर बनी बांस की बखारी, गाय, बैल, भैंस आदि मवेशियों को खाने के लिए बने नाद तथा घर के चारो ओर पर्याप्त खाली जगह घर के अनिवार्य हिस्सा हुआ करते थे, जहां जिंदगी खुलकर सांस लिया करती थी और बच्चे खेलते-कूदते, उछलते-कूदते, डेंगा-पानी और लूका-छिपी का खेल खेलते थे। ये

सब बढ़ी हुई आबादी को एकोमोडेट करने में गुम हो गये। यहां तक की घर से आंगन भी गायब हो गई है। यही कारण है कि अब तुलसी का पौधा आंगन में नहीं, बालकनी में नजर आते हैं। पहले जगह की कोई कमी नहीं थी, इसलिए पहले रसोईघर इतना बड़ा होता था कि उसमें बैठकर महिलाएं गपशप किया करती थी, अब टी.बी. और मोबाइल पर बात करने तथा वाट्सअप देखने में मशगूल रहती हैं। हर तरफ बढ़ते अपार्टमेंट कल्चर ने यदि सबसे अधिक किसी को प्रभावित किया है तो वह है छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियां। दिवारों से घिरे अपार्टमेंट के कैदनुमा फ्लैट में न पर्याप्त हवा मिलती है और न रौशनी। कमरो में रौशनी के लिए दिन में भी बल्ब जलाने पड़ते हैं। फिर कमरे भी आकार में काफी छोटे बने हुए हैं। नतीजा मासूम बच्चों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। उन्हें उछलने-कूदने, दौड़ने आदि के लिए जगह की बहुत कमी पड़ गई है। ऐसे में कैसे खिलेगा मासूमों का बचपन। पहले सभी जगह खुले मैदान थे, बच्चों को खेलने की आजादी थी। जनसंख्या विस्फोट के चलते अब वह मैदान मकानों और अर्पाटमेंट में तब्दील हो गये हैं। ऐसे में बच्चे खेले तो कहां खेले। जगह के आभाव में आदमी अब घर के बजाय कबूतरों के दड़बो जैसे बने अपार्टमेंट के फ्लैटों में रहने को मजबूर हो गया है। जनसंख्या विस्फोट के चलते अब तो प्लैट का मिल जाना भी दुर्लभ हो गया है। ऐसे में व्यक्तित्व का विकास भला संभव है? व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त खुली जगह की जरूरत पड़ती है। फिर पहले संयुक्त परिवार होने के चलते एक ही परिवार में खेलने के लिए बच्चों की कमी नहीं होती थी। अब एकल परिवार में परिवार नियोजन के चलते बच्चों को खेलने के लिए बच्चों के लाले पड़ गये हैं। नतीजा बच्चे संस्कारवाण बनने के बजाय कुसंस्कारी बनते जा रहे हैं, अपनेपन की भावना का लोप होता जा रहा है। समाज स्वर्ग बनने के बजाय नर्क बनता जा रहा है। दरअसल प्रकृति से दूर घर में कैद मंहगे कृत्रिम साजो-समान जैसे-घर की दीवारों पर लटकाई गई जंगलों, झड़नों, पहाड़ों आदि की सुंदर तस्वीरों, कागज व प्लास्टीक के बने सुंदर फूलों और पत्तियों के गुच्छों, टी.बी. , लैपटॉप, मोबाइल आदि के बीच रहकर कोई अपने भीतर सकारात्मक विचारों और भावनाओं को कैसे गढ़ पायेगा। ऐसे में भला आकर्षक व्यक्तित्व का विकास कैसे संभव हो पायेगा?

☞ **चारित्रीक पतन की समस्या उत्पन्न हो गई है :-** जनसंख्या विस्फोट के चलते जगह की इतनी कमी हो गई है कि आज हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे खेल-कूद नहीं पा रहे हैं। हम प्राकृतिक जिंदगी जीने के बजाय कृत्रिम जीवन जीने को मजबूर हो गये हैं। ऐसे में हमारा रहन-सहन

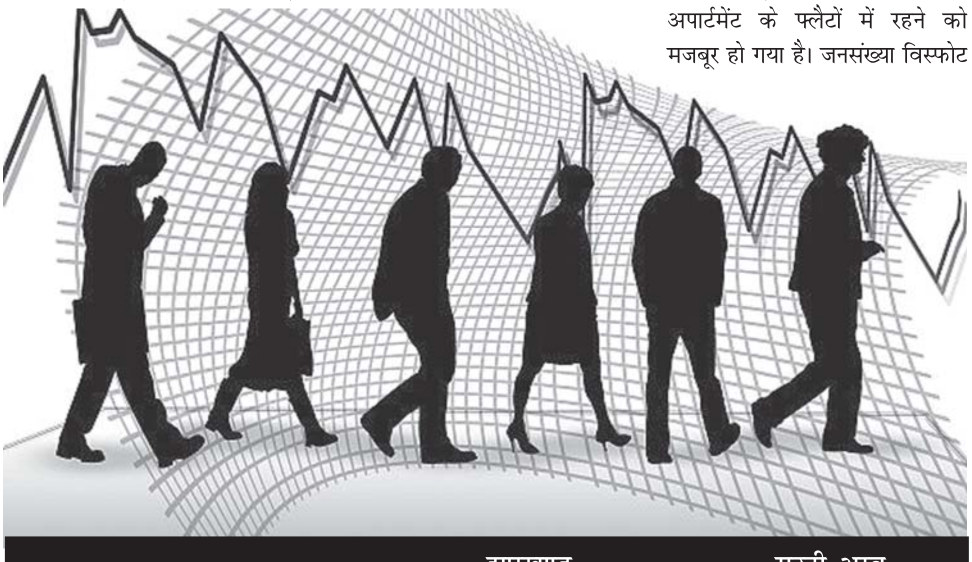

	झारखण्ड	सउदी अरब
क्षेत्रफल	97 हजार 714 वर्ग कि०मी०	21 लाख 50 हजार वर्ग कि०मी०
आबादी	3 करोड़ 33 लाख	3 करोड़ 35 लाख 54 हजार
प्रति व्यक्ति जमीन	0.002 वर्ग कि०मी	0.064 वर्ग कि०मी०
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय	62 हजार 186 रूपये	31 लाख 37 हजार 752 रूपये
	बिहार	**इथोपिया**
क्षेत्रफल	94 हजार 163 वर्ग कि०मी०	11 लाख 04 हजार वर्ग कि०मी०
आबादी	10 करोड़ 41 लाख	10 करोड़ 6 लाख 14 हजार
प्रति व्यक्ति जमीन	0.0009 वर्ग कि०मी	0.019 वर्ग कि०मी०
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय	38 हजार 546 रूपये	37 हजार 752 रूपये

स्वभाविक कम दिखावती ज्यादा हो गया है। हमारे बीच अपनापन की भावना बहुत तेजी से लुप्त होती जा रही है। हम पास-पास होते हुए भी बहुत दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में भला व्यक्तित्व का विकास कैसे संभव हो पायेगा? हम सुसंस्कृत और चरित्रवान कैसे बन पायेंगे? अर्थात् व्यक्तित्व के समुचित विकास हेतु पर्याप्त जगह चाहिए ही चाहिए, जो जनसंख्या विस्फोट के चलते संभव नहीं हो पा रहा है। परिणाम भी हमारे सामने है। हम अधिकाधिक हिंसक और ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं। हम दूसरो की भलाई करने के बजाय बर्बाद करने में संलिप्त होते जा रहे हैं। नतीजा मामूली से मामूली बात को लेकर लात-घूंसा, धक्का-मुक्की करने लगते हैं। अब तो ऐसा दृश्य रोजाना संसद और एसेम्बली में देखने में मिल जाता है। जनता की समस्या को लेकर संसद और ऐसेम्बली में वाद-बिवाद बहुत ही कम और बेहुदा हरकत करते हुए बहुत अधिक देखने को मिलता है, लेकिन आज सरकार और समाज दोनो को ही इस तथ्य को समझना होगा कि व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त जगह का होना अनिवार्य है।

☞ **दुनियां में सबसे अधिक बेरोजगारों का देश है भारत :-** जिस युवा शक्ति के दम पर हम दुनियां भर में इतराते फिरते हैं और इसे अपना सर्वाधिक प्रमुख संसाधन मानते हैं, वही युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर-दर भटक रही है। दरअसल विगत पांच दशकों में आबादी में निरंतर बेतहाशा वृद्धि के चलते जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्ष 2017 में देश के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर 2013-14 में बढ़कर 4.9 फिसदी पहुंच गयी, जो 2012-13 में 4.7 फिसदी थी। सीसीआई की इंडिया स्कील रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ 25 लाख शिक्षित युवा तैयार होते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.86 करोड़ तक रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019 में 1.89 करोड़ तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है। पिछले तीन सालों में बेरोजगारी की दर में जर्बदस्त इजाफा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में हमारे देश में कई करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बढ़ती बेरोजगारी के चलते सबसे अधिक आत्म-हत्याओं का कलंक हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल हो गई है कि देश में शांति तथा कानूनी व प्रशासनिक व्यवस्था को जर्बदस्त खतरा पैदा हो गया है। हर छोटी-छोटी बात को लेकर तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाएं अब आए दिन घटने लगी है। यह हालात तब है, जब देश में बेरोजगारी से निपटने के लिए ढ़ेर सारे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंति रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजागार योजना (मनरेगा), इत्यादि।

दरअसल, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के अधिकत्तर नागरिकों को रोजगार मिले, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति गलत राह पर चलने को मजबूर हो जाता है। कहावत है कि ''मरता क्या नहीं करता'' अर्थात् जब मर ही रहे हैं तो कोई भी अपराध करने में कोई हर्ज नहीं है। बात यह है कि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है, जब वहां के नागरिकों के पास आजिवीका का कोई न कोई साधन अवश्य उपलब्ध हो। दरअसल में हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए हमारे पास रोजगार का कोई न कोई विकल्प होना अनिवार्य है। हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार की जरूरत होती है। बिना रोजगार के किसी भी मनुष्य के सामने अपने अस्तित्व को बचाये रखने का संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में मनुष्य अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है, जो देश और समाज की प्रगति में न सिर्फ बाधक सिद्ध हो रहा है, बल्कि पतन की ओर ले जा रहा है।

☞ **चरमरा गई है शिक्षा व्यवस्था :-** इतनी बड़ी आबादी के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था को किया जाना संभव नहीं रह गया है। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था का भी लगभग खास्ता हाल हो चुकी है। सरकार इस बात की ओर ध्यान देती है कि स्टूडेंट्स को मीड-डे भोजन जरूर मिले, पहनने के लिए पोशाक भी जरूर मिले। घर से स्कूल आने-जाने के लिए साईकिल भी जरूर मिले, पर्याप्त संख्या में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशीप जरूर मिले, इत्यादि। लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर के रूप 90 फिसदी बाबा जी मिले, योग्य शिक्षक नहीं मिले। अर्थात् स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई को छोड़कर हर सहुलियत मिली। दो-तीन कमरो में 90 फिसदी स्कूल चलाये जा रहे हैं-सरकारी हो या प्राइवेट। किसी-किसी स्कूल को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों में बच्चों को खेलने-कूदने के लिए कोई जगह नहीं है। भयावह बेरोजगारी के चलते प्राइवेट स्कूलों में कम से कम पैसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में जो सर और मैडम मिल जाते हैं, उनमें 90 फिसदी सर और मैडम ऐसे होते हैं, जिन्हें एक लाइन शुद्ध-शुद्ध न पढ़ना आता है और न लिखना। ऐसे में अधिकतर बच्चे सिर्फ बेहूदा बन जाते हैं।

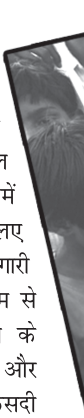

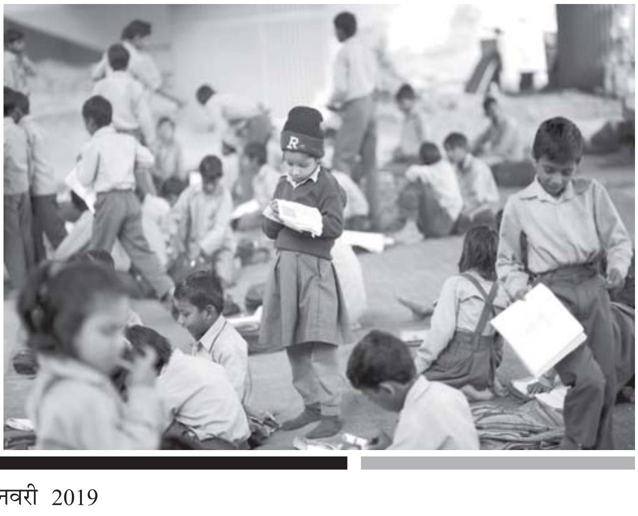

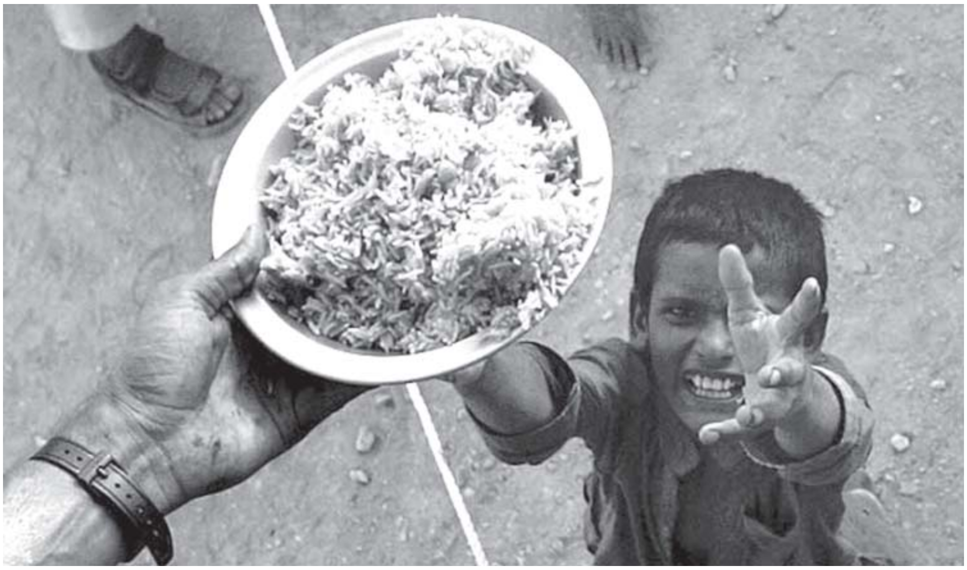

अर्थात् घर और समाज दोनो के लिए सिरदर्द। बिहार सरकार भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में 90 फिसदी ऐसे सर और मैडम को बहाल कर रखी है, जो पढ़ाई-लिखाई में एकदम से बाबाजी हैं। यदि समाज के निर्माता टीचर ही बकलोल होंगे तो बच्चे नालायक नहीं तो और क्या होंगे? हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स बगैर लेबोरेट्री में गये ही फर्स्ट डिवीजन में पास कर जाते हैं। शिक्षा का स्तर आज इतना गिर चुका है कि लगभग 90 फिसदी शिक्षित बेरोजगार डिग्रीधारी युवक-युवतियां काम पाने के योग्य नहीं है। नतीजा सफाईकर्मी और चपरासी की नौकरी के लिए बी.एड., एम.एड., बी.सी.ए, एम. सी.ए., बी.बी.ए., एम.बी.ए., यहां तक की पी.एच.डी. धारियों में जबर्दस्त

प्रतिर्स्पधा है।

अगर चपरासी की दो हजार भेकैंसी निकलती है तो उस नौकरी को पाने के लिए ऐसे लाखों डिग्रीधारी आवेदन कर देत हैं। इनमें से 90 फिसदी डिग्रीधारी स्कूलों में नामांकन हेतु बच्चों का एडमिशन फॉर्म भी भरने में सक्षम नहीं होते हैं अर्थात् ढ़ंग की नौकरी पाने के लिए 90 फिसदी तथाकथित शिक्षित बेरोजगार डिग्रीधारी योग्य नहीं है, फिर भी शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा एक भी ठोस व कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं और जो भी उठाये जा रहे हैं, उसका कार्यान्वयन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पढ़े-लिखे अयोग्य बेरोजगारों की फौज अपराध और आत्म-हत्या करने के बजाय और करेगा क्या? शिक्षा के स्तर को इस हद तक गिराने में सरकार और समाज दोनो ही बराबरी के साझेदार हैं। इसलिए नितांत जरूरी है कि शिक्षा के स्तर को सुधारकर बेरोजगारों को रोजगार के लायक बनाने की। शिक्षा के गिरते स्तर के कारण देश के समाजिक और आर्थिक विकास पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रोजगार पाने की जर्बदस्त प्रतिर्स्पधा के वर्तमान दौर में शिक्षा का स्तर इतना उच्च व व्यवसायिक होना चाहिए कि शिक्षा पूरी करते-करते बेरोजगार शिक्षित युवा अपने हाथ में आये काम को पूरे आत्म-विश्वास

के साथ पूरा करने में सक्षम हो सके। ऐसा होने पर रोजगार पाने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ देश और समाज का चौमुखी विकास होना निश्चित है।

☞ **भूखमरी की समस्या विकराल हो रही है :-** संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट के चलते एशिया में 7 करोड़ 90 लाख पांच साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 48 करोड़ 60 लाख की आबादी भूख से जुझ रही है। बढ़ी हुई आबादी को एकोमोडेट करने हेतु खेती की जमीन कम होती जा रही है। आबादी की वृद्धि के चलते खाद वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में हम भूखमरी के कगार की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

☞ **भयंकर जल संकट के मुआने पर पहुंच गयी है दुनियां :-** पूरी दुनियां में करीब 210 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है आर भारत में करीब 90 करोड़ लोगों को। दुनियां के लगभग एक चौथाई शहर (कम से कम 200 शहर) जल संकट का सामना कर रहे हैं। दुनियां के करीब 35 मेट्रो शहरों में जल संकट की स्थिति भयावह है। इस दृष्टि से भारत की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर है। इस सूचि में भारत के चार शहर बेंग्लुरू, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद भी शामिल है। तमाम अनुमान बता रहे हैं कि 2020 तक यानि

वर्ष 2018 में दुनियां के टॉप 4 आबादी ग्रोथ वाले देश

देश	कुल आबादी	वृद्धि दर	बढ़ी आबादी
चीन	141 करोड़	0.39%	55 लाख
भारत	135 करोड़	1.11%	1.48 करोड़
अमेरिका	32.6 करोड़	0.71%	23 लाख
इंडोनेशिया	26.6 करोड़	1.06%	28 लाख

देश	आबादी (फिसदी में)	आबादी (करोड़ में)	जमीन की हिस्सेदारी (फिसदी में)	आबादी का घनत्व (लोग प्रति व्यक्ति वर्ग कि०मी०में)	जीडीपी (रूपये में)	आय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रूपये में)
चीन	18.54	141	6.3	151	962 लाख करोड़	6 करोड़ 90 लाख
भारत	17.74	135	2.0	455	192 लाख करोड़	1 करोड़ 40 लाख
अमेरिका	4.28	33	6.1	36	1327 लाख करोड़	40 करोड़ 90 लाख
इंडोनेशिया	3.50	17	1.2	147	73 लाख करोड़	2 करोड़ 80 लाख
ब्राजील	2.76	21	5.6	25	144 लाख करोड़	7 करोड़ 10 लाख
पाकिस्तान	2.63	20	---	---	---	---
नाइजीरिया	2.57	19	---	---	---	---
बंगलादेश	2.18	17	---	---	---	---
रूस	1.89	14	---	---	---	---
मैक्सिको	1.71	13	---	---	---	---

आने वाले महज दो साल में दिल्ली सहित देश के 21 शहरों में भू-जल समाप्त हो जायेगा, तो ऐसे में इन शहरों में रहने वाले लगभग 10 करोड़ की आबादी के लिए मुसीबतें खड़ी हो जायेगी। दुनियां के करीब 50 करोड़ लोग सालों भर पानी की व्यापक कमी से जुझते रहते हैं। असुरक्षित जल की उपलब्धता जीवन व्यतित करने वालों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। भारत और अफ्रिका के 40 फिसदी बच्चे गंदे पानी के सेवन से अविकसित रह जाते हैं। विकासशील देशों में कुल बीमारी का 80 फिसदी हिस्सा प्रदुषित जल के सेवन से होता है। वर्ष 2002-03 में पूरी दुनियां में दुषित जल और खराब सफाई से 22 लाख लोगों की मौत हुई थी। अब तो पूरी दुनियां में 25 लाख लोग हर साल स्वच्छ पेयजल के आभाव में जान गवां देते हैं।

हमारे देश के लगभग 70 फिसदी इलाके में पानी की कमी है और लगभग 51 फिसदी इलाका सूखे से जुझ रही है। दुनियां की करीब 18 फिसदी आबादी भारत में रहती है। लेकिन यहां दुनियां में इस्तेमाल योग्य पानी का महज 4 फिसदी ही पानी उपलब्ध है। जबकि देश में बेतहाशा बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में कुल 640 जिले हैं। जिनमें से 302 जिले कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं और 256 जिले सूखा प्रभावित इलाके में आते हैं। महज 82 जिले ऐसे हैं, जहां इस्तेमाल योग्य पानी की उपलब्धता कामचलाउ है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां इस्तेमाल योग्य पानी की उपलब्धता कामचलाउ से ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के रिसोर्स मिनिस्ट्री के अनुसार 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 6043 घन मीटर थी। वर्ष 2016 में जब हमारे देश की आबादी 120 करोड़ हो गई तो पानी की उपलब्धता घटकर 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई। अर्थात् आजादी के बाद के 69 वर्षों में पानी की उपलब्धता में 75 फिसदी की कमी हो गई। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि आबादी के वृद्धि के साथ-साथ पानी की खपत हर साल बढ़ रही है। पिछली एक सदी में पानी की खपत 6 गुना से भी अधिक बढ़ी है।

कुल वैश्विक भू-जल का 72 फिसदी लगभग तीन चौथाई का उपयोग भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सहित दस देशों मं होता है। लेकिन पूरी दुनियां में भारत भू-जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम चीन और अमेरिका से दोगुने से भी अधिक भू-जल का दोहन करते हैं। अकेले भारत में सलाना 35 बीसीएम (बिलियन क्यूबीक मीटर) भू-जल का दोहन होता है, जबकि चीन और अमेरिका मिलकर सालाना 11.5 बीसीएम भू-जल का दोहन करते हैं। वर्ष 2017 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार हमारे देश में पिछले दस वर्षों में भू-जल के स्तर में 61 फिसदी की कमी आयी है। 2012 के रिपोर्ट के अनुसार भू-जल के कुल वैश्विक इस्तेमाल का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा भारत उपयोग में लाता है। भारत के ग्रामीण इलाके जरूरत के पानी का 85 फिसदी हिस्सा पानी की आपूर्ति भू-जल के द्वारा किया जाता है और शहरी इलाकों में जरूरत का 55 फिसदी हिस्सा पानी की आपूर्ति भू-जल से किया जाता है। ऐसा इसलिए की भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के ज्यादातर हिस्से में सिंचाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है।

भू-जल के बेलगाम दोहन के चलते भू-जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। भू-जल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि बिहार के जमुई जिले के कुछ प्रखण्डों में भू-जल का स्तर एक हजार फीट से भी अधिक नीचे चला गया है। पाताल से पानी दोहन करने के लिए धरती छलनी कर दी गई है। भू-जल के दोहन हेतु सिर्फ पटना शहर में हर साल कई हजार सबमर्जिबल मोटर पम्प गाड़े जा रहे हैं। बेतहाशा भू-जल दोहन के चलते पटना शहर में भू-जल

का स्तर सालाना 4 से 6 फीट नीचे जा रहा है। शहर में 14 घंटे पानी की आपूर्ति समझ के बाहर है। दरअसल लोगों में पानी स्टोर करने की प्रवृति नहीं है। यही कारण है कि पटना नगर निगम को दो चरणों के बजाये चार चरणों में पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है, जबकि 1970 तक इसी शहर में केवल दो चरणों में चार-चार घंटे ही पानी की आपूर्ति की जाती थी। अपार्टमेंट कल्चर में भू-जल का अंधाधूंध दोहन हो रहा है। हजारों अपार्टमेंट में भू-जल दोहन चौबिसों घंटे जारी रहता है। इससे पता चलता है कि हमारा समाज भू-जल के दोहन में कितना निष्ठुर और गैरजिम्मेदार है। अर्पाटमेंट, बहुमंजिली इमारत तथा बड़े-बड़े सरकारी और गैर सरकारी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा दूसरे भू-जल रिचार्ज सिस्टम नहीं लगाये गये हैं। जबकि ऐसा किया जाना कानूनी अनिवार्य माना गया है।

☞ **जनसंख्या नियंत्रण का कोई विकल्प नहीं :-** जनसंख्या नियंत्रण का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हर हालत में जनसंख्या नियंत्रित करना ही होगा। बात यह है कि वर्तमान में देश की आबादी बहुत अधिक है। इतनी अधिक है कि लोगों की सहुलियत के लिए जितना भी किया जा रहा है, सब कम पड़ता जा रहा है। खाने के लिए अनाज कम पड़ गया है, पीने के लिए पानी कम पड़ गया है, रहने के लिए मकान कम पड़ गया है, शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान कम पड़ गये हैं, इलाज के लिए अस्पताल कम पड़ गये हैं, खेलने-कूदने के लिए खेल के मैदान कम पड़ गये हैं, आवागमन तथा माल की ढुलाई के लिए रेल, बस, कार, हवाई जहाज, ऑटो, बाईक आदि सब के सब कम पड़ गये हैं। घूमने के लिए पार्क कम पड़ गये हैं, खेती के लिए जमीन कम पड़ गई है, सड़क-पुल आदि के लिए जमीन कम पड़ गई है, शुद्ध हवा के लिए तथा जल संरक्षण के लिए पेड़-पौधे कम पड़ गये है, जल संरक्षण के लिए तालाब कम पड़ गये हैं, नौकरी के लिए खाली पद (वेकेंसी) कम पड़ गये हैं, जलाने के लिए बिजली कम पड़ गई है, वाहनों को दौड़ाने के लिए सड़क कम पड़ गई है, पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे स्थित फुटपाथ कम पड़ गये हैं, नदियों को पार करने के लिए पुल कम पड़ गये हैं, इत्यादि। अर्थात् जीवन के हर क्षेत्र में हमें कमी का सामना करना पड़ रहा है या कमी झेलने के लिए हम मजबूर हैं। अर्थात् जनसंख्या विस्फोट के चलते हमें हर तरह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हर हालत में जनसंख्या को नियंत्रित करना ही होगा।

✯ **जनसंख्या नियंत्रण के कारगर व व्यवहारिक उपाय :-** हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है। ऐसे में आगामी दस-बीस वर्षो तक कोई बच्चा पैदा न भी हो तो हम पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। सरकार को कुल मिलाकर जनसंख्या नियंत्रण हेतु ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो कारगर व व्यवहारिक हो तथा मानवता की दृष्टि से उचित हो और जिनका कार्यावरण आसानी से किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी

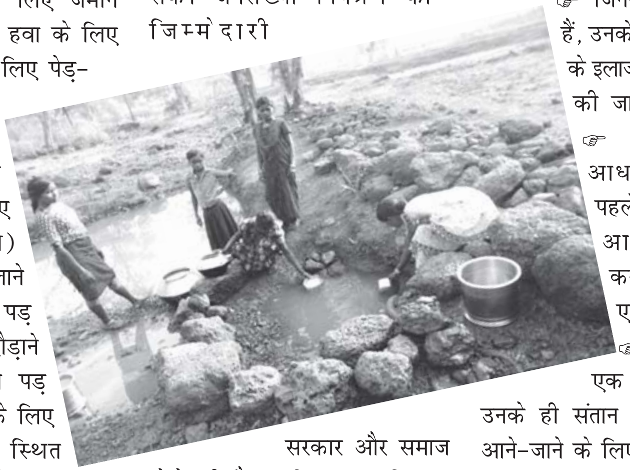

सरकार और समाज दोनो की है। इसलिए इस पुणित व अति अनिवार्य कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार और समाज दोनो को साथ मिलकर जीतोड़ प्रयास करना चाहिए। सरकार को "हम दो हमारे एक" के सिद्धांत पर कानून बनानी चाहिए और उसे सख्ती से लागू भी करना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग "हम दो हमारे एक" के सिद्धांत पर चलने के लिए जनता मजबूर हो जाये। जनसंख्या नियंत्रण के कारगर व व्यवहारिक उपाय है :-

☞ लड़का-लड़की मिलकर जिनके दो से अधिक संतान हैं, उनको सरकार चुनने हेतु वोट देने से अधिकार से वंचित कर देना चाहिए।

☞ जिनको दो से अधिक संतान हैं, उनको और उनके संतानों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

☞ जिनको दो से अधिक संतान है, उनके संतानों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिले पर रोक लगा देनी चाहिए।

☞ जिनकी एक ही संतान हैं, उनके तथा उनके संतान के इलाज की मुफ्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

☞ प्राथमिकता के आधार पर सरकार पहले उन्ही को पहले आवास उपलब्ध करावे, जिनकी सिर्फ एक ही संतान है।

☞ जिनकों सिर्फ एक ही संतान है, सिर्फ उनके ही संतान को स्कूल/कॉलेज आने-जाने के लिए तथा नौकरी पाने हेतु इंटरव्यू व परीक्षा देने के लिए बस, ट्रेन और हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा कर सके, इसकी व्यवस्था करायी जानी चाहिए।

☞ जिनको एक ही संतान है, उनके संतान को शिक्षा मुफ्त में दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

☞ विधायक और सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ने हेतु केवल उन्ही व्यक्तियों को टिकट दी जानी चाहिए, जिनकी सिर्फ एक ही संतान है।

☞ जिनको दो से अधिक संतान है, उनके संतानों को पढ़ाई हेतु किसी भी तरह का सरकारी अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए।

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :- www.psfsm.in

रोगों से सुरक्षा के लिए जरूरी है हांथ धोने की आदत डालना

● ललन कुमार प्रसाद

अच्छी सेहत के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन जरूरी माना गया है, लेकिन भोजन का स्वच्छ और पौष्टिक होना तब बेइमानी हो जाता है, जब हांथ स्वच्छ न हो। अधिकतर लोग हांथों की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं जबकि काम करते समय हांथ ही सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। हांथ ही सबसे अधिक जीवाणु, विषाणु, किटाणु और रोगाणु के सम्पर्क में आते हैं। खासकर बच्चे ऐसी गलती सबसे अधिक करते हैं। इसलिए बच्चे ही सबसे अधिक सर्दी-जुकाम, निमोनिया, फ्लू, डायरिया, पिलिया, उल्टी, भूख की कमी, वर्म (पेट के कीड़े) आदि अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। इसके दो कारण है-पहला की खेलने के बाद बच्चे अक्सर बगैर हांथ धोवे ही खाने या नास्ता करने बैठ जाते हैं तथा यदा-कदा कुछ-कुछ खाते रहते हैं, खासकर ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में बच्चे तो क्या, बड़े भी भोजन करने के पहले हांथ धोने से कतराते हैं, जो निश्चित रूप से अच्छी आदत नहीं है। दूसरा की बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि स्कूलों में बच्चों की गैरहाजिरी की सबसे बड़ी वजह वे बीमारियां हैं, जो हांथ न धोने के कारण होती है। पटना (बिहार) के पेट रोग विशेषज्ञ पद्म श्री डॉ० विजय प्रकाश का मानना है कि साबुन से हांथ धोकर भोजन करने से 50 फिसदी तक पेट की बीमारियों से निजात मिल जाती है। फोर्टिस अस्पताल, नोयडा के डॉ० शिखर गर्ग बताते हैं-''अच्छी तरह से हांथ धोकर भोजन करने मामूल सर्दी-जुकाम से लेकर खतरनाक बुखार तथा अन्य कई बीमारियों से परिवार को बचा सकते हैं।'' हांथ साफ रखने से यानि हांथ धोने से जलजनित मौतें 35 फिसदी कम हो जाती है। लंदन में हुए एक रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि सभी लोग जरूरत के मुताबिक उचित समय पर हांथ धोने लगे तो हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। इसलिए हम सबों को, खासकर बच्चों को हांथ धोकर भोजन या कुछ भी खाने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि अच्छी तरह से हांथ धोकर भोजन करना कई बीमारियों से बचने का रक्षा कवच है। सिर्फ अच्छी तरह से हांथ धोने से ही हम समान्य सर्दी-जुकाम से लेकर दिमागी बुखार इन्फ्लूएंजा और संक्रमण दस्त से बच सकते हैं। इसलिए हांथ धोने की अहमियत को नजरंदाज नहीं करे। हांथ की सफाई पर लगाये गये चंद सेकेण्ड आपको और आपके बच्चों को डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने से बचा सकते हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को खाने से पहले और खाना खाने के बाद हांथ धोना सिखाए। हर रोज उचित समय पर हांथ धोने की आदत को जीवनशैली में शामिल करे।

बच्चों को हांथ धोकर ही छुएं :- अक्सर देखा गया है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद ही कुछ लोग, जैसे परिवार और रिश्तेदार के लोग बच्चे को छुने और चुमने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्यार जताना कई बार नवजात को गंभीर बीमारियों का शिकार बना देता है। दरअसल, माँ के गर्भ में बच्चों को वैक्टेरिया, वायरस, वर्म्स और जर्म्स का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए जन्म के समय उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन जन्म के बाद जैसे-जैसे उनका सामना सुक्ष्म जीवाणुओं से होता है, वैसे-वैसे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है। इसलिए नवजात शिशु की देखभाल में अतिरिक्त सफाई का पालन करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर उनमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए सफाई का ध्यान बच्चे के जन्म से ही दिया जाना चाहिए। नवजात शिशु को छुने से पहले हांथ को साबुन लगाकर अच्छी तरह से

धो लेना चाहिए। जिस कमरे में बच्चों को जन्म हुआ हो, उस कमरे में जूता, सैंडल और चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज भी गांवों में प्रसव घर में ही करा दिया जाता है, जहां पर्याप्त साफ-सफाई नहीं रहती है। फिर कई बार नवजात शिशु को ऐसी फटी-पुरानी सारी या चादर में लपेट दिया जाता है, जो पर्याप्त साफ नहीं होती है। इतना ही नहीं कई बार नवजात की नाल काटने के लिए नये ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में नवजात में हेपेटाइटिस होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रसूता की देखभाल के दौरान एक ही कपड़े या टिसु से बच्चे और माँ की सफाई कर दी जाती है, जो संक्रमण का कारण बनता है।

ऑपरेशन थियेटर में सर्जन ऑपरेशन प्रारंभ करने के पहले साबुन से हांथ धोने के बाद साफ तौलियां से हांथ पोछकर ही सर्जिकल दास्ताने पहनते हैं। जबकि प्रत्येक ऑपरेशन शुरू करने के पहले ऑपरेशन थियेटर और सर्जरी के उपकरण स्टरलाइज्ड कर लिए जाते हैं। डॉक्टर चाहे कितना भी रगड़कर हांथ धोए लेकिन पूरे वैक्टेरिया कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। हांथों को पूरी तरह से स्टरलाइज्ड करना संभव नहीं है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन के पहले हांथों में सर्जिकल दास्ताने पहनते हैं। दरअसल, कोशिश यही रहती है कि कम से कम संक्रमण मरीज तक पहुंचे।

सर्दी-जुकाम, निमोनिया, फ्लू, दम फूलना, एलर्जी आदि बीमारियां केवल हांथ न धोने, शरीर का सही तरीके से सफाई न करने और निवास स्थान को साफ-सुथरा नहीं रखने के कारण फैलती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड प्रिवेंशन के अनुसार सही तरीके से हांथ नहीं धोकर खाने के कारण खाने से जुड़ी 50 फिसदी बीमारियां होती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के संक्रमण में गंदे हांथों की भूमिका अहम होती है। गंदे हांथों से चिपके वैक्टेरिया, वायरस, किटाणु और रोगाणु खाना खाते समय, नाक पोछते समय और आंख मलते समय हांथों से हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जो हैं। ऐसे में सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां तो आसानी से व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेती है। इतना ही नहीं, बच्चों में निमोनिया और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी गंदे हांथ की वजह से सबसे अधिक होती है।

अहमियत हांथों की सफाई का :- अच्छी सेहत के लिए हांथ की सफाई की अहमियत कितनी है, इसकी झलक युनिसेफ की रिपोर्ट से मिलती है। इसमें कहा गया है कि शौच के बाद केवल सही तरीके से हांथ धोने से डायरिया का खतरा 40 फिसदी और श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा 30 फिसदी कम हो जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड प्रिवेंशन के मुताबिक सही तरीके से हांथ नहीं धोने के कारण 50 फिसदी बीमारियां होत है। बच्चा पैदा होते समय डॉक्टर और नर्स अपनी हांथों को साबुन से अच्छी तरह धो ले तो शिशु मृत्यु दर में 19 फिसदी की कमी हो जाती है।

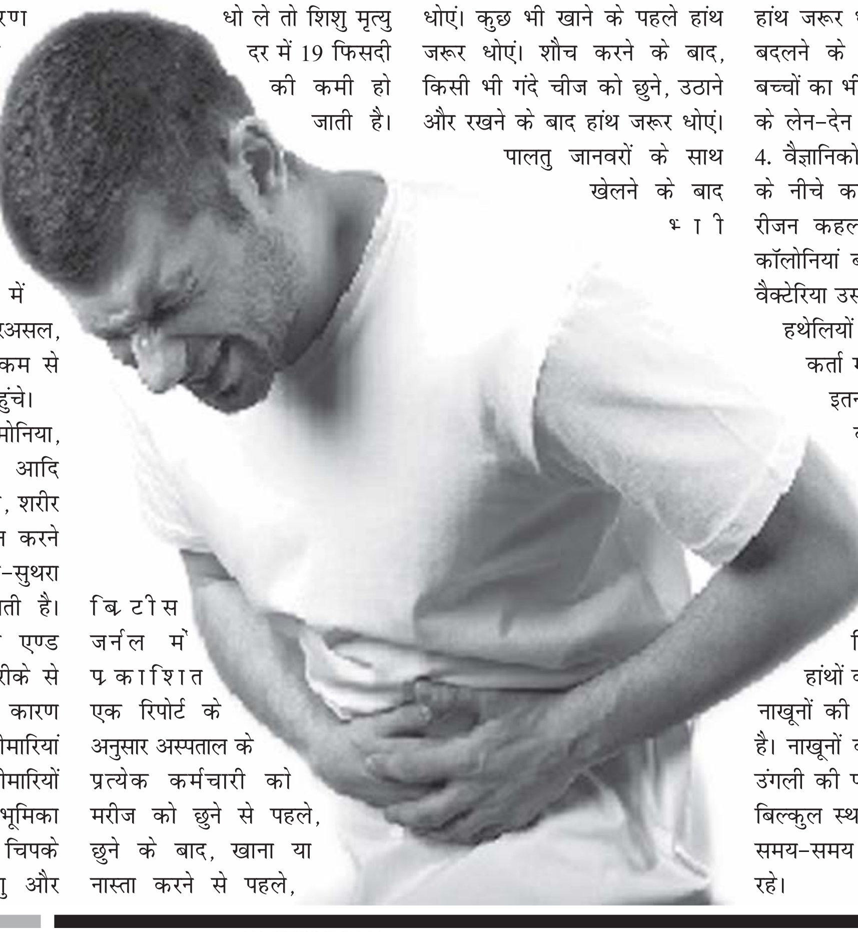

ब्रिटीस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को मरीज को छुने से पहले, छुने के बाद, खाना या नास्ता करने से पहले, शौच से आने के बाद साबुन से हांथ धोने से संक्रमण के चलते होने वाली मौतों पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। श्वास विशेषज्ञों का कहना है कि हांथों को साफ रखने से टायफायड, हेपेटाइटिस-ए, इबोला, कंजंक्टिवाइटिस आदि जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सकता है।

सजकता से लगेगी हांथों की सफाई की आदत :- आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में हुए एक अध्ययन के अनुसार मात्र पांच फिसदी लोग ही सही तरीके से हांथ धोते हैं, जबकि हांथ की सफाई हेतु बहुत पैसे का खर्च नहीं करने पड़ते हैं। बस थोड़ी सी सजकता के साथ कुछ नियमों को जीवन में उतारने की जरूरत है।

हांथ की सफाई हेतु जरूरी है निम्न बातों का ख्याल रखना :-

1. भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हांथ जरूर धोएं, खासकर जब कच्चा मांस, मछली, अंडे आदि बनाने के बाद हांथ अवश्य धोएं। कुछ भी खाने के पहले हांथ जरूर धोएं। शौच करने के बाद, किसी भी गंदे चीज को छुने, उठाने और रखने के बाद हांथ जरूर धोएं। पालतु जानवरों के साथ खेलने के बाद भी हांथों की सफाई जरूरी है। गाय, बैल और भैंस का गोबर तथा घोड़े का बिष्ठा उठाने के बाद हांथ अवश्य धोएं।

2. घर के आसपास गली-कूची में कूड़े-कचड़े अक्सर इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं। जमीन पर बिखरे धूल में कुत्ते, गाय, घोड़े, बकरी, बिल्ली आदि जानवरों के बिष्टा भी मिले होते हैं। गली और सड़कों के किनारे गई जगहों पर नालियां खुली रहती है, जिनमें खेलते समय गेंद अक्सर चले जाते हैं। जिसे बच्चे हांथ से निकालकर गेंद और बगैर हांथ धोएं ही पुनः खेलने लगते हैं। खेलने के दौरान बच्चे बार-बार ऐसा करते हैं, जिससे उनके हांथ बुरी तरह से गंदे हो जाते हैं। इसलिए खेलने के बाद बच्चों को अपने हांथों की सफाई साबुन लगाकर अच्छी तरह से कर लेना चाहिए।

3. फोड़े-फूंसी और जले-कटे घाव की मरहम-पट्टी व साफ-सफाई के बाद हांथ अवश्य धोएं। नाक पोछने, छिकने और खासने के बाद हांथ जरूर धोएं। बच्चों का डायपर बदलने के बाद अपने साथ-साथ बच्चों का भी हांथ धोएं। रूपया-पैसा के लेन-देन के बाद भी हांथ धोएं।

4. वैज्ञानिकों ने पाया है कि नाखूनों के नीचे का हिस्सा जो सबफिंगर रीजन कहलाता है, वहां वैक्टेरिया कॉलोनियां बनाकर बस जाते हैं। ये वैक्टेरिया उसी प्रजाती के होते हैं, जो हथेलियों पर मौजूद रहते हैं। शोध कर्ता मानते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी भारी संख्या में मिलने का कारण यह है कि बैक्टेरिया को नाखूनों का सुरक्षा कवच मिल जाता है तथा ग्रोथ के लिए जरूरी नमी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। इसलिए हांथों की सफाई के साथ-साथ नाखूनों की सफाई भी बेहद जरूरी है। नाखूनों को इतना छोटा रखे की उंगली की पोर और नाखून के बीच बिल्कुल स्थान शेष न रहे। इसलिए समय-समय पर नाखूनों को काटते रहे।

5. साबुन और पानी से हांथ धोना सिर्फ पानी से हांथ धोने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि साबुन आपके हांथ में लगी मिट्टी के साथ-साथ किटाणुओं को भी साफ कर देता है।

6. सेनिटाइजर्स का इस्तेमाल यथा संभव कम करे, क्योंकि प्राय: इसको हांथ सुखने के पहले ही लोग पोंछ देते हैं। फिर सेनिटाइजर्स की तुलना में साबुन पानी या लिक्विड हैंडवॉश से हांथों को धोया जाना ज्यादा प्रभावी होता है।

7. अक्सर हम हांथ धोते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि हम कैसे और कितने समय तक हांथ धोना चाहिए। जब हम हांथ धोते हैं तो साबुन या लिक्विड हैंडवॉश का इस्तेमाल इस तरह करे कि झाग अच्छी तरह से बन जाये। फिर झाग को अच्छी तरह से दोनो हांथों में लगावे और अंगुलियों के बीच की पोर तथा नाखूनों के भीतर दोनो हांथों से मिलाकर कम से कम 15-20 सेकेंड तक रगड़ें। हांथ धोने के बाद साफ और सूखे तौलिया से हांथों को अच्छे से पोछे। हांथ हमेंशा साफ तौलियां से पोछे, क्योंकि यदि तौलियां गंदा हो तो किटाणु दोबारा आपके हांथों में चिपक जाते हैं। इसलिए हांथ धोने के स्थान पर हांथ पोछने के लिए दो साफ तौलिया इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हांथ धोने के स्थान पर साबुन या लिक्विड हैंडवॉश जरूर होने चाहिए। जिस पानी से हांथ धो रहे हैं, वह साफ होना चाहिए।

8. अक्सर देखा गया है कि हांथ धोने का संकेत लगा देने से हांथ धोने की अवधि और फ्रिक्वेंशी दोनो बढ़ जाती है।

साफ-सफाई के फायदे :-

1. स्वच्छ शरीर व स्वच्छ कार्य स्थल, चाहे वह घरा हो या कार्यालय, स्कूल हो या कॉलेज, प्रयोगशाला हो पुस्तकालय, होटल हो या हॉस्पीटल, रेलवे स्टेशन हो या सिनेमा हॉल, बस अड्डा हो या हवाई अड्डा, दुकान हो या बाजार, पोस्ट ऑफिस हो या म्यूजीयम, गोदाम हो या स्टेडियम या कोई अन्य कार्य स्थल, न आपको तरोताजा और खुश रखता है बल्कि आपके आत्म-विश्वास और कार्य क्षमता को बढ़ाता भी है। साफ-सुथरे स्थान पर करीने से सजाकर रखे गये स्थल आकर्षक व दर्शनीय दिखते हैं।

2. साफ-सुथरा रहने वाले लोग तथा साफ-सुथरा मुहल्लों में रहने वाले लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टरों और दवाईयों पर खर्च बहुत कम होता है। अत: पैसों की अच्छी खासी बचत होती है और बेकार की परेशानी से हम बच जाते हैं।

3. साफ-सुथरा कोई समान हो या व्यक्ति, अपनी विशिष्ट पहचान बना ही लेता है। यही कारण है कि जिन मुहल्लों में साफ-सफाई रहती है और जिन मुहल्लों के लोग साफ-सुथरा रहते हैं, वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, हमेशा तरोताजा और प्रसन्न रहते भी है और दिखते भी हैं। इसलिए ऐसे मुहल्लों की गिनती वीआईपी मुहल्लों में की जाती है और ऐसे लोगों को समाज में वीआईपी का दर्जा प्राप्त होता है।

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट :-
www.psfsm.in

आप भी बनें पत्रकार

भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टों के खिलाफ बेझिझक कलम उठाईये। बेरोजगारी के अभिशाप को मिटायें। देश के सभी प्रदेश की राजधानी और देश के सभी प्रदेश के शहरों में संवाददाता की आवश्यकता है। कर्मचारी नहीं हिस्सेदार बने। जितना श्रम उतना पारिश्रमिक पायें।

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308/9308727077

नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

● **अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

बीते 12 दिसम्बर 2018 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत अर्राबाड़ी स्थित डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन फीता काटकर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक भवन का मुआयना किया। उन्होंने डिजिटल क्लास रुम, एग्रीकल्चरल एनटोमोलॉजी, इनसेक्ट्स म्यूजियम एवं कम्प्यूटर लैब का भी मुआयना किया एवं विभिन्न चीजों की जानकारी प्राप्त की। महाविद्यालय परिसर में ही स्थित कृषि विकास मेला 2018 का मुख्यमंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इसमें सामाजिक परिवर्तन के लिए चलायी जा रही ई–तालिम शिक्षा, जीविका, महिला उत्पादक समूहों द्वारा तैयार की गई चीजें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज, मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज के द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर विशेषज्ञों से भी मुख्यमंत्री ने जानकारी प्राप्त की। सनद् रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों को वाहन वितरित किया एवं कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के बाद दी जाने वाली राशि से संबंधित चेक भी कन्या के माता–पिता को दिया गया। वही कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि लोकल दलहन की प्रजाति को फिर से स्थापित करने के लिए काम करें। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बीजों की प्रजाति विकसित करें। कृषि मेले में भ्रमण के पश्चात मुख्यमंत्री ने महानंदा नदी पर बनाए गए तटबंध का भी निरीक्षण किया। साथ ही कलाम कृषि महाविद्यालय परिसर में बने अन्य भवनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का भी वाहन से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के समक्ष नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में ही डॉ0 कलाम महाविद्यालय के विस्तार से संबंधित रोड मैप का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण में इस महाविद्यालय से जुड़े हुए छात्रावास, स्पोर्ट्स क्लब, चिकित्सा केंद्र, अतिथि गृह, परिसर में कर्मियों के बच्चों के लिए बनाए गए स्कूल, सुविधा केंद्र के बारे में विस्तार से बताया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के तहत किये जा रहे प्रयासों के बारे में भी चर्चा हुई। खेती के लिए उन्नत तकनीक, फसलों के विकास के लिए शोध के संबंध में जानकारी दी गई। कौशल विकास के तहत चलाए गए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी प्रस्तुतीकरण में जानकारी दी गयी। प्रस्तुतीकरण में शामिल अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बी0एस0सी0 एग्रीकल्चर का फाइनल बैच अब पास आउट होने वाला है, उसके बाद आई0सी0ए0आर0 को एक्रेडेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि यहां छह विषयों (विभाग) में पी0जी0 एवं रिसर्च से संबंधित पढ़ाई होगी। फिशरीज से संबंधित प्रस्तुतिकरण भी दी गई। प्रस्तुतिकरण

को ध्यान से देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज का साइट बहुत ही उत्तम है। बगल में महानंदा नदी है, यहां का वातावरण भी मनोरम है। किशनगंज को भी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रुप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कैम्पस की बाउंड्री के किनारे–किनारे पेड़ लगाने की जरुरत है ताकि यह क्षेत्र हरा–भरा दिखे। यहां जमीन की लेबलिंग जल्द से जल्द करायी जाए। उन्होंने कहा कि इस परिसर में बड़े–बड़े तालाब बनवाने की जरुरत है। पांच एकड़ के तालाब में सोलर प्लांट लगाएं, जिसमें नीचे मछली का उत्पादन हो और ऊपर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो। उन्होंने कहा कि इस परिसर में जितनी भी बिल्डिंग बनी हैं, उन सारी बिल्डिंगों के ऊपर सोलर प्लेट लगवाएं, उससे उत्पादन होने वाली बिजली की खपत इस परिसर में हो और बची हुयी बिजली को ऊर्जा विभाग के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा की जरूरत पर बल देते हुये कहा कि यहां बनाए जाने वाले तालाब में पानी भरने के लिए सोलर पंप ही लगवायें। उन्होंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए बनाए जाने वाले कॉलेज के लिए प्लांट को और बड़ा बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में वृद्धि हो ताकि उसका एक्सपोर्ट किया जा सके। यहां के किसानों का रुचिकर फल है पाईन एप्पल, इसको भी विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि यहां जो तटबंध बने हैं, उससे बगल के गांव और खासकर इस संस्थान की सुरक्षा होगी। मुख्यमंत्री के समक्ष कम्युनिटी साइंस, होम साइंस का अलग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा

गया, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां इसका सेंटर पहले खुलवाइये उसके बाद वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करे तो इस सेंटर को विकसित कर कॉलेज रुप में परिणत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि यहां बैंक का ब्रांच जरुर खुलवायें। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निर्देश दिया और कहा कि इस परिसर में जहां बालू अधिक है वहां परवल, खीरा, तरबूज जैसे फलों का उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म के लिए किशनगंज बेहतर साइट प्रतीत होता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत अंगवस्त्र, पुष्प–गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉ0 प्रेम कुमार, सांसद श्री संतोष कुशवाहा, विधायक श्री मुजाहिद आलम, विधायक श्री नौशाद आलम, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रूकैया बेगम, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद महमूद अशरफ, जदयू जिलाध्यक्ष श्री फिरोज अंजुम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव कृषि श्री सुधीर कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन डॉ0 एन0 विजया लक्ष्मी, कोसी प्रमंडल की आयुक्त डॉ0 सफिना ए0एन0, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉ0 अजय कुमार सिंह, डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के अधिष्ठाता एवं प्राचार्य प्रो0 यू0एस0 जायसवाल सहित अन्य प्राध्यापकगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मिथिला को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में शामिल :-मुख्यमंत्री

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

बीते 10 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड स्थित सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान एवं मिथिला ललित संग्रहालय के भवन का रिमोट बटन दबाकर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उदघाट्न भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि मिथिला चित्रकला संस्थान एवं मिथिला ललित संग्रहालय के भवन का कार्यारंभ कराया गया। भवन निर्माण विभाग ने अगस्त 2020 तक इसे बनाने के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2012 में मधुबनी पेंटिंग की मूल चीजों को समझने के लिए हमने रांटी, जितवारपुर आदि गांवों का दौरा किया था। पद्मश्री सुंदरी देवी के आवास पर भी जाने का मौका मिला। मिथिला पेंटिंग के कलाकारों से भी मुलाकात की थी। स्व0 ताराकांत झा जी के साथ–साथ लोगों ने भी इच्छा जतायी थी कि मिथिला पेंटिंग संस्थान की यहां स्थापना हो। उन्होंने कहा कि 19 जून 2012 में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना का ऐलान किया गया था। सितंबर 2013 में मंत्रिमंडल से भी इसकी स्वीकृति मिल गई। इसके साथ–साथ मिथिला ललित संग्रहालय के बारे में भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्माण कहां हो और कैसे हो, इसके लिए लोगों से परामर्श किया गया। डी0पी0आर0 तैयार किया गया, सभी चीजों के आकलन के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सौराठ के संस्कृत विद्यालय के एक हिस्से के साढे सात एकड़ में इस संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। सारी तैयारियों के बाद आज इसका शुभारंभ हुआ है।

गौरतलब है कि मिथिला चित्रकला के लिए 13 छात्र–छात्राओं का चयन किया गया, जिसमें 11 लड़कियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि मिथिला चित्रकला संस्थान के लिए किराए पर एक भवन लेकर इन छात्र–छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। इस संस्थान में पढ़ाने वाले आचार्य का चयन मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में सम्मानित लोगों के बीच से किया जायेगा, जिनको मिथिला पेंटिंग की बेहतर जानकारी होगी उन्हें रखा जाएगा, इसके लिए विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मिथिला चित्रकला संस्थान एवं मिथिला ललित संग्रहालय को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला चित्रकला के लिए दो तरह के कोर्स चलाये जायेंगे। एक सर्टिफिकेट कोर्स (छह माह) होगा और एक डिग्री कोर्स होगा। सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स करने वालों को आर्थिक सहायता भी दी जायेगी। साथ ही निःशुल्क हॉस्टल एवं मेस का प्रबंध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस भवन के डिजाइन की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला पेंटिंग के प्रति पूरे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी लोगों का लगाव है। उन्होंने कहा कि हम फरवरी 2018 में जापान की यात्रा पर गए थे, उस समय जापान में भारत के राजदूत श्री सुजान आर0 चिनॉय थे, जिनकी भी रुचि मिथिला पेंटिंग में रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के टोकामाची सिटी में मिथिला म्यूजियम है, जिसके निदेशक टोक्यो हासेगावा हैं, वहां मिथिला पेंटिंग का अद्भुत कलेक्शन है। वहां जाने की मेरी इच्छा थी लेकिन अधिक दूरी और अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होने

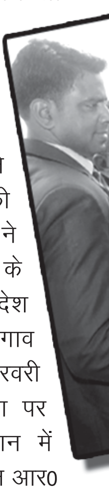

के कारण मैं नहीं जा सका। टोक्यो के विवेकानंद कल्चर सेंटर में राजदूत श्री सुजान आर0 चिनॉय ने मिथिला म्यूजियम की पेंटिंग की यहां प्रदर्शनी दिखाई थी, वह अद्भुत था। जापान से लौटने के बाद मिथिला चित्रकला संस्थान एवं मिथिला ललित संग्रहालय को जल्द शुरु करने का निर्णय लिया गया। आज छात्र–छात्राओं का चयन कर सांकेतिक रुप से शुरुआत कर दी गई है। मिथिला पेंटिंग के जो तीनों प्रारुप हैं, उसमें सभी समाज के लोग हैं। मधुबनी पेंटिंग का जो ओरिजिनल नेचर है, उसको रखा जाएगा और मिथिला कला को और विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे।

बताते चले कि पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किए जाने की बात मुख्यमंत्री कही तथा आगे बताया कि उसकी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर और बाहर मिथिला पेंटिंग की झलक देखने को मिलेगी। दरभंगा में एयरपोर्ट का भी निर्माण एयरफोर्स बेस में हो रहा है। बाहर के

जिन लोगों की रुचि मधुबनी पेंटिंग में होगी, दरभंगा से सिविल विमानन सर्विस शुरु होने से आसानी से यहां आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर भी मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में संकल्प भवन की दीवारों पर भी मिथिला पेंटिंग करायी गई है। पटना शहर में सभी सरकारी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग करायी जा रही है। हमलोगों की मधुबनी पेंटिंग के प्रति बहुत श्रद्धा है, आप सबलोगों के सहयोग से इसे और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि देश का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक की बिहार का विकास नहीं होगा और बिहार का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक कि मिथिला का विकास नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के अन्य हिस्सों के साथ–साथ मिथिला में भी पुल–पुलियों सहित निर्माण के कई कार्य किये जा रहे हैं। हम एरियल सर्वे के द्वारा इन सब चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। अभी मानसी–सहरसा–सुपौल में आपसी कनेक्टिविटी के एलाइनमेंट का एरियल सर्वे करके आ रहे हैं। इंडो–नेपाल एरिया का भी अभी एरियल सर्वे करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हर घर तक बिजली पहुंच गई है और बिजली की आपूर्ति भी ठीक ढंग से हो रही है। पहले बिजली की जगह लोग ढिबरी और लालटेन से काम चलाया करते थे। लोगों में अंधेरे और भूत का डर बना रहता था। रौशनी नहीं होने के कारण घर के बच्चे संकट में रहते थे, अब अंधेरा भी खत्म हुआ और लालटेन

की जरुरत भी नहीं रही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में टकराव पैदा करना चाहते हैं, उनसे सचेत रहें और समाज में सद्भाव एवं प्रेम का माहौल बनाए रखें। समाज में जब शांति का वातावरण रहेगा तो विकास का लाभ लोगों तक और तेजी से पहुंचेगा। लोग किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, सबको अपनी आस्था का अधिकार है लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी जरुरी है। हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। हम न्याय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समाज के हर तबके और राज्य के हर इलाके के विकास में हम लगे हुए हैं। सात निश्चय के अंतर्गत गांवों का विकास किया जा रहा है और वहां के लोगों को हर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद यहां के छात्र–छात्राएं आगे पढ़ सकें, इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को चार प्रतिशत और छात्राओं, ट्रांसजेडरों और दिव्यांगों को एक प्रतिशत के ब्याज पर 4 लाख रूपये तक शिक्षा ऋण मुहैया करा रही है। शिक्षा ग्रहण के बाद जब ये काम करने लगेंगे तो उन्हें 82 किस्तों में पैसे लौटाने होंगे और अगर पैसे लौटाने में अक्षम होंगे तो इस ऋण को माफ भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित लोगों से हाथ उठाकर संकल्प दिलाया कि वे अपने बच्चों को आगे जरुर पढ़ायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ज्ञान की भूमि है, यहां के लोग खूब पढ़ें, इसमें मेरी रुचि है। हम फिर से बिहार के गौरव को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। हमारी प्राथमिकता की सूची में मिथिला को आगे बढ़ाना भी शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत पाग, अंगवस्त्र, पुष्प–गुच्छ, मखाने की बड़ी माला एवं मिथिला पेंटिंग भेंटकर किया गया। मुख्यमंत्री ने क्रॉफ्ट डिमोंस्ट्रेशन के तहत लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी के सर्टिफिकेट कोर्स का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भूमिहीनों के बीच वासगीत पर्चा का भी वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम को पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि, भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य श्री संजय झा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक श्री लक्ष्मेश्वर राय, विधान पार्षद श्री राम लषण राम, विधान पार्षद श्री दिलीप कुमार चौधरी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती भारती मेहता, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव पथ निर्माण श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव कला एवं संस्कृति श्री रवि मनुभाई परमार, भवन निर्माण विभाग के एम0डी0 श्री अमित कुमार, दरभंगा के आयुक्त श्री मयंक बरबरे, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री पंकज दराद, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मधुबनी के जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक बर्णवाल सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485

E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ जमानत और बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध (Provisions as to Bail and Bonds)

☞ चार्जशीट आने के बाद जमानत धारा 437 के अन्तर्गत गुणागुण के आधार पर ही जती है।

☞ धारा 436 (1), 437 के अन्तर्गत जमानत केवल मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी दे सकता है।

☞ धारा 439 के अन्तर्गत सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय जमानत देता है।

☞ धारा 438 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत का अन्तरिम आदेश उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय देते हैं।

☞ अग्रिम जमानत तब तक प्रभावी होती है, जबतक अभियुक्त का विचारण समाप्त न हो जाये या न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाये।

☞ न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण न्यायिक अभिरक्षा माना जाता है।

☞ उच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का उपबन्ध नहीं है।

☞ जमानत का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त और जमानतियों से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि वे विचारण के समय उपलब्ध रहेंगे।

☞ जमानतीय मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत देने से इन्कार करने पर पुलिस अधिकारी धारा 432 दण्ड संहिता के अन्तर्गत सदोष परिरोध के लिए उत्तरदायी होता है।

☞ जमानतीय मामले में जमानत को विचारण न्यायालय खारिज नहीं कर सकता है।

☞ धारा 482 के अन्तर्गत तथा उच्च न्यायालय को धारा 436 के अन्तर्गत जमानत खारिज करने को अन्तर्निहित शक्ति है।

☞ जमानत खारिज हो जाता है, तो खारिजी के आदेश के लिए न अपील होगी न पुनरीक्षण।

☞ जमानत का आदेश अन्तर्वर्ती आदेश है।

☞ जमानत का आवेदन खारिज हो जाता है, तो पुन: आवेदन उसी न्यायालय में दिया जा सकता है, जिसने जमानत को आवेदन खारिज किया है। जमानत के सम्बन्ध में प्राय: लागू नहीं होता है।

☞ धारा 395 के अन्तर्गत निर्देश न्यायालय, धारा 397 के अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालय तथा धारा 389 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय जमानत का आदेश देते हैं।

☞ विशेष परिस्थितियों में कुछ निश्चित समय के लिए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना पैरोल कहलाता है। पैरोल शर्ट टर्म बेल होता है। जब साधारण जमानत का आवेदन खारिज हो जाता है, तो पैरोल का आवेदन दिया जाता है।

विचारण (Trials)

☞ पूर्वदोषसिद्धि का साक्ष्य लेने का प्रावधान समन मामले के विचारण में नहीं है।

☞ समन मामले में दण्ड के प्रश्न पर नहीं सुना जाता है।

☞ समन मामले का वारण्ट मामले जैसा विचारण किया जाता है और अभियुक्त उन्मोचित हो जाता है तो उन्मोचन दोषमुक्ति माना जायेगा।

☞ अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसे दोषसिद्धि का दण्डादेश दिया जा सकता है।

☞ अभियुक्त किसी ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जा सकता है, जिसका परिवाद या समन में उल्लेख नहीं है लेकिन जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है। (धारा 255(3))

☞ जहाँ किसी परिवाद पर सम्मन जारी किया जाय और समन में नियत किये गये दिन को परिवादी उपस्थित न हो, तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। (धारा 258)

☞ धारा 256 के प्रावधान केवल परिवाद पर संस्थित किये गये मामलों पर ही प्रयोज्य होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किये गये मामलों पर नहीं।

☞ परिवादी अन्तिम आदेश पारित किये जाने से पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है। (धारा 257)

☞ परिवाद वापस लेने का प्रभाव दोषमुक्ति होता है।

☞ परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य मजिस्ट्रेट कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में निर्णय सुनाये बिना रोक सकता है। (धारा 258)

☞ 6 मास के कारावास से दण्डनीय अपराध का विचारण न्यायहित में वारण्ट मामले के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। (धारा 259)

☞ समन मामले में आरोप विरचना आवश्यक नहीं होता है।

☞ समन मामले में विचारण का प्रारम्भ तब माना जाता है जब अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियाँ बतायी जाती है। (धारा 251)

☞ समन मामले में उन्मोचन नहीं होता है। अर्थात् समन मामला एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।

☞ वारण्ट मामले का समन मामले की तरह विचारण या समन मामले का वारण्ट मामले की तरह विचारण एक अनियमितता है और धारा 465 द्वारा ठीक होने योग्य है, विचारण दूषित नहीं होता जब तक पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

☞ संक्षिप्त विचारण (धारा 260 से धारा 265 तक)

☞ संक्षिप्त विचारण में तीन मास से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता है। (धारा 262(2))

☞ संक्षिप्त विचारण की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।

☞ संक्षिप्त विचारण साधारणत: समन मामले का किया जाता है। कुछ वारण्ट मामले का भी विचारण किये जाने का प्रावधान धारा 260 में है।

☞ यदि मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण के लिए प्राधिकृत नहीं है फिर भी अपराध का संक्षिप्त विचारण करता है, तो विचारण शून्य होगा। (धारा 461)

☞ उच्च न्यायालय द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रकार के अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं–

(1) जो केवल जुर्माने से दण्डनीय हो।

(2) जो जुर्माने सहित या रहित 6 मास तक के कारावास से दण्डनीय है।

(3) उपर्युक्त अपराधों के दुष्प्रेरण या अपराधों को करने के प्रयत्न के अपराध।

कर्मियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी करे : मुख्य सचिव

● अमित कुमार/ब्रजेश कु० मिश्रा

बीते वर्ष 10 दिसम्बर 2018 को झारखण्ड प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी राँची स्थित प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब होते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की प्रोन्नति की जिला स्तर पर लंबित मामलों की प्रक्रिया जल्द पूरी करें, ताकि देय राशि माह के अंत तक मिल जाए। उन्होंने ठंड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण सुनिश्चित करें। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत इनपैनल स्वास्थ्य केंद्रों में जहां चिकित्सकों की कमी महसूस हो, वहां स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों की सेवा का प्रबंधन करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन निजी चिकित्सालयों पर भी नजर रखने की जरूरत बताई, जहां आयुष्मान भारत के लाभुकों को योजना से बाहर निजी स्तर पर इलाज की बातें सामने आ रही हैं। इस दौरान सचिवों ने अपने-अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं पर क्रियान्वयन से जुड़ी अपेक्षाएं बताईं, वहीं उपायुक्तों की सलाह भी सुनी गई। बताते चले कि मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत क्लेम की संख्या बढ़ाएं। कहा, देखने में आ रहा है कि निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना की प्रक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन क्लेम जेनरेट नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव नितीन मदन कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में 238 निजी अस्पतालों ने इनपैनल के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि वे इनकी क्षमता की जांच कर जो अप टू मार्क नहीं हैं उन्हें खारिज करें और जो अप टू मार्क हैं, उन्हें इनपैनल करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। वहीं स्कूली विद्यार्थियों को असेंबली के दौरान डीवर्मिंग की दवा खिलाने का निर्देश दिया। गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने केंद्रीय टीम द्वारा सूखा प्रभावित जिलों के दौरे के बाद सुखाड़ प्रभावित किसानों, मजदूरों और बच्चों को लाइवलीहुड के लिए प्रतिदिन नगद राशि देने के लिए यथाशीघ्र उनकी लिस्ट देने का निर्देश दिया। बताया कि 30 से 90 दिन तक प्रति व्यस्क प्रति दिन 60 रुपये तथा बच्चों को 45 रुपये देय होगा। वहीं अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा से जुड़े मामलों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक ने ओडीएफ घोषित गांवों के बाकी बचे शौचालयों के फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया, ताकि यह कार्य 90 फीसद पूरा होने पर केंद्र सरकार से राशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि यह कार्य 80 फीसद पूरा हो चुका है। उन्होंने ओडीएफ की घोषणा के बाद नया घर बनानेवालों द्वारा शौचालय निर्माण की मांग को स्वीकार करने का भी निर्देश दिया। वहीं गोवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने पर बल देते हुए योजना से स्वंय सहायता समूहों को जोड़ने का निर्देश दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन ने भू अर्जन से जुड़े मुख्यमंत्री जनसंवाद में आए सभी मामलों को विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, ताकि मुख्यालय से समेकित रूप से मामलों का त्वरित निबटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राजस्व कर्मियों की हड़ताल से लंबित आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम को नवनियुक्त 659 कर्मियों से कराने का निर्देश दिया। उपायुक्तों से कहा कि उन्हें नियमित प्रभार देते हुए हल्का का जिम्मा दें तथा रिकार्ड भी उपलब्ध कराएं। वहीं जो हड़ताली कर्मचारी काम पर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दें। वहीं मानकी-मुंडा को भुगतान करने तथा टाना भगत विकास प्राधिकार की 10 करोड़ की राशि के सदुपयोग का निर्देश दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्र निर्धारण की लिस्ट यथाशीघ्र भेजने का निर्देश उपायुक्तों को दिया। बताया कि 11 जिलों के परीक्षा केंद्रों में स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। निर्देश दिया कि बाकी बचे 13 जिलों के परीक्षा केंद्रों में भी स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। कहा, इससे स्कूलों की नियमित गतिविधि की मॉनिटरिंग सहज होगी। उन्होंने स्कूली बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया को और तेज करने पर बल देते हुए जानकारी दी की इस मसले को कोर्ट में ले जानेवालों को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जुर्माना किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि गलत ढंग से राशन कार्ड लेनेवाले अगर 31 दिसंबर तक खुद अपना कार्ड सरेंडर करते हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन इस बीच जांच में पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। उन्होंने घर में अकेले रहनेवाले गरीब वृद्धों पर नजर रखने तथा उन्हें खाद्यान्न योजना का नियमित लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान लेकर आनेवाले किसानों के भुगतान पर बल दिया। साथ ही इसकी जानकारी सभी किसानों को हो इसके लिए एसएमएस आदि की सहायता लेने को कहा। उन्होंने कतिपय मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे दुष्कर्म पीड़िताओं के सामाजिक बहिष्कार से जुड़े मामले की दंडाधिकारी से जांच करा कर रिपोर्ट दें।

टाना भगतों की सभी जमीन लगान मुक्त होगी : सुधीर

● धीरज कुमार/शशांक पाठक

21 दिसम्बर 2018 को झारखण्ड प्रदेश की राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सचिवालय सभागार में संपन्न बैठक में राजस्व सचिव केके सोन, टाना भगतों के प्रतिनिधि समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी के समक्ष टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि टाना भगत विकास प्राधिकार का मूल मकसद टाना भगतों को स्वावलंबी बनाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना है। इसके लिए सरकार ने टाना भगतों की पूरी जमीन लगान मुक्त कर दी है। लगान रसीद पर भी निःशुल्क लगान अंकित रहेगा। इसके लिए ऑनलाइन लगान साफ्टवेयर भी संशोधित किया गया है। पहले 10 एकड़ भूमि तक एक रुपये का टोकन लगान निर्धारित था। मुख्य सचिव ने टाना भगतों की मांग पर उनके बाकी बचे कुल परिवारों और जनसंख्या को रिकार्ड में लाने का निर्देश दिया। उन्होंने टाना भगतों द्वारा जिलावार इस आशय की सूची उपलब्ध कराने पर उसकी जांच कराकर या उपायुक्तों के संज्ञान में आने पर राजस्व विभाग को सूची भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टाना भगतों की जमीन से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करने के बाद सरकार अब उनके घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली–पानी आदि मूलभूत जरूरतों पर फोकस कर रही है। मुख्य सचिव ने उत्तराधिकार के आधार पर टाना भगतों की जमीन का दाखिल–खारिज कैंप लगाकर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने टाना भगतों को सूची संबंधित जिले के उपायुक्तों को उपलब्ध करने को कहा। बैठक में टाना भगतों को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत

दो की जगह तीन कमरे बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए प्रति कमरा 70 हजार रुपये की राशि भी आवंटित की जा चुकी है। वहीं 641 टाना भगत परिवारों को निःशुल्क चार दुधारू गाय देने और गायों के लिए शेड निर्माण की राशि भी विमुक्त की जा चुकी है। लाभुकों को गोपालन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। टाना भगतों को अपनी पसंद की नस्ल की गाय खरीदने के लिए तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में संबंधित विभाग द्वारा समुचित सहयोग का भरोसा दिया गया। वहीं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सरकार के खर्चे पर अध्ययनरत टाना भगत विद्यार्थियों के प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिया गया। वही मुख्य सचिव ने दसवीं से कम पढ़े टाना भगतों की स्क्रीनिंग कर कौशल विकास मिशन द्वारा शीघ्र प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं, बैठक में टाना भगत महिलाओं को चरखा का प्रशिक्षण देने पर सहमति बनी। इसके लिए खादी बोर्ड से समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त विभागीय योजनाओं के तहत खाद–बीज, सिंचाई, कुंआ, तालाब निर्माण जैसे लाभ देने पर भी सहमति दी ।

मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जायेगा : सुनील वर्णवाल

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

राज्य के मीडिया कर्मियों को सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ेगी। मीडिया कर्मी और उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने बीते वर्ष 2018 के 8 दिसम्बर को सूचना भवन में एक बैठक में यह बात कही। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा के तर्ज पर ही मीडिया कर्मियों को भी स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अधिक से अधिक

मीडिया कर्मी को इसका लाभ मिल सके। इसके कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की बैठक में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं इन सुझावों पर भी समग्रता से विचार कर जल्द ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसे कार्यान्वित करेगी। प्रधान सचिव ने कहा कि अत्यंत दुष्कर परिस्थितियों में भी मीडिया रिपोर्टिंग का कार्य करना तथा राज्य हित में जनहित में खबरों का प्रसारण करना मीडिया की चुनौती रही है। इनके स्वास्थ्य बीमा से इन्हें भी इलाज के लिए सुविधा मिलेगी। बैठक में दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर, झारखंड सतीश सिंह हिंदुस्तान के प्रधान संपादक के प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक संपादक चंदन मिश्र, न्यूज18 के ब्यूरो प्रमुख राजेश तोमर, जी मीडिया के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

इंकलाब जिन्दाबाद	इंटक जिन्दाबाद	मजदूर एकता जिन्दाबाद

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

यदि आप कैजूअल/दैनिक/ठीका मजदूर के रूप में निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत्त हैं, इसके अतिरिक्त होटल रेस्तरां, अस्पताल-स्कूल, अन्य संस्थान निर्माण/बीड़ी क्षेत्र, स्थानीय निकाय, लोडिंग-अनलोडिंग, केन्द्र/राज्य सरकार के स्कीम्स एवं अन्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत्त हैं, साथ ही वेंडर्स, घरेलू कामगार, रिक्शा/टेम्पो/टैक्सी चालक हैं तो अपने हक एवं अधिकार के साथ ही मजूदरी के निर्धारण, काम की सुरक्षा, कानून अंतर्गत सुविधायें एवं ईपीएफ/ईएसआई का लाभ प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) से संबंद्ध श्रमिक संघों से जुड़ें एवं मजदूर आन्दोलन को ताकत दें।

चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रदेश अध्यक्ष (इंटक) बिहार।

Website :-www.prakashintuc.com
Mob.:- 9431016951, 9334110654
E-mail :-chandraprakash.intuc@yahoo.com

पानी टंकी वाटर बोर्ड कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना-800013 (बिहार)

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट
www.shruticommunicationtrust.org

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- Sector - 1, Block - 14, Flat No.- 501, Khelgaon Houseing Colony, Hotwar, Ranchi
Mob.- 9431073769, 9308727077